● वर्ष-4
● अंक-135
रायपुर, गुरुवार 16 जनवरी 2025
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6» बीमा प्रीमियम कैलकुलेटर

दीक्षांत समारोह में शामिल हुए उपराष्ट्रपति

नये भारत में युवाओं के लिए असीमित अवसर:धनखड़

रायपुर । उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने आज गुरू घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर के 11 वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि की आसंदी से सम्बोधित करते हुए कहा कि आप सब युवा नये भारत के राजदूत हैं। देश को आपको अपना शत-प्रतिशत देना होगा। कोई भी व्यक्तिगत हित राष्ट्र हित से बढ़कर नहीं है। युवाओं को अपने चारों ओर देखना होगा, सिर्फ सरकारी नौकरियां ही जीवन का लक्ष्य न हो। युवाओं के पास अब नये भारत में धरती से लेकर आकाश तक असीमित अवसर हैं।

उप राष्ट्रपति ने कहा कि बाबा गुरु घासीदास एकता और समानता के प्रतीक थे। हमें उनकी शिक्षाओं और संदेशों का अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने युवाओं को बदलते तकनीक से तालमेल बैठते हुए कौशल एवं नवाचार के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि जीवन में कभी भी असफलता से घबराएं नहीं बल्कि उससे सीख लेते हुए आगे बढ़ें। उन्होंने समारोह में सत्र 2022-23 के 78 एवं सत्र 2023-24 के प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 77 विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक, 09 दानदाता पदक, 01 गुरू घासीदास पदक तथा 01 कुलाधिपति पदक सहित 85 पदक प्रदान किये गये। इसके साथ ही सत्र 2022-23 एवं सत्र 2023-24 के कुल 122 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई।

उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ ने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज बाहुल्य राज्य है। यहां समृद्धि की काफी संभावनाएं हैं, इसलिए विकास की ऐसी रणनीति बनाएं जिससे सामूहिक समृद्धि बढ़े और जन-जन का विकास संभव हो। उन्होंने कहा कि विगत वर्ष में नक्सली उन्मूलन की दिशा में काफी अच्छे प्रयास हुए हैं और इन क्षेत्रों में विकास की रफ्तार भी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि अभूतपूर्व विकास वाले राज्य में नक्सलवाद के लिए कोई जगह नहीं है। इस समय जो विकास हो रहा है, वह समाज के हाशिये पर पड़े वर्गों, समाज के कमजोर तबके पर केन्द्रित है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी जन हितैषी नीतियों और कार्यक्रमों से राज्य के समग्र विकास को एक नई दिशा दी है।

राज्यपाल श्री रमेन डेका ने कहा कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, एक ऐसी संस्था है जिसने लगातार छत्तीसगढ़ में शिक्षा और ज्ञान के मार्ग को रोशन किया है। राज्यपाल ने कहा कि स्वर्ण पदक और पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने वालों के वर्षों के समर्पण, लगन और कड़ी मेहनत का प्रतिफल है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि विविधता का सम्मान करें और देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखें।

कवासी लखमा बेटे सहित गिरफ्तार

शराब घोटाला मामले में ईडी का एक्शन

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित दो हजार करोड़ के शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और बेटे हरीश लखमा को गिरफ्तार किया गया है। बुधवार को कवासी लखमा ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए पहुंचे हुए थे, जहां उनकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरी ओर ईडी दोनों को लेकर कोर्ट में पेश करने के लिए रवाना हो गई है। इसकी पुष्टि ईडी के वकील सौरभ चंद्राकर ने की है। बता दें कि शराब घोटाला मामले में कवासी लखमा से इससे पहले दो बार ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की थी। यह तीसरी पूछताछ थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी के दफ्तर पहुंचने से पहले लखमा ने कहा था कि आज पूछताछ के बुलाया गया था, इसलिए आया हूं। देश कानून के हिसाब चलता है। अगर कानून के हिसाब से बुलाएंगे, तो मैं 25 बार आऊंगा। ईडी के अधिकारी जो सवाल करेंगे, उसका जवाब दूंगा। उनका सम्मान करुंगा।

पूर्व आबकारी मंत्री लखमा और सीए को ईडी ने पूछताछ के लिए बुयाला था। इस संबंध में लखमा ने बताया कि उनके सीए बाहर हैं, इस वजह से वह नहीं आए हैं। लखमा अकेले दफ्तर पहुंचे हुए थे। जानकारी के अनुसार, 28 दिसंबर को ईडी ने कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा के ठिकानों में छापेमार कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई के बाद ईडी ने

नगद लेनदेन के सबूत मिलने की जानकारी दी थी। इससे पहले दो बार लखमा से ईडी आठ-आठ घंटे पूछताछ की थी। वहीं आज बुधवार को तीसरी और चार घंटे पूछताछ के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया है।

लखमा ने खुद को निर्दोष बताया

अदालत ले जाते समय लखमा ने खुद को निर्दोष बताते हुए संवाददाताओं से कहा कि मेरे पास से एक पैसा भी नहीं मिला है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया है। मैं उनका सहयोग कर रहा था। भाजपा मेरे जैसे गरीब आदमी को झूठा फंसा रही है। लेकिन मैं बस्तर के मुद्दे उठाता रहूंगा। 28 दिसंबर को ईडी ने लखमा से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की, जिसमें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में उनका आधिकारिक आवास और सुकमा में उनके बेटे हरीश का आवास भी शामिल था। ईडी की छापेमारी के बाद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, लखमा ने कहा उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मुझे शराब घोटाले के बारे में पता है। मैंने कहा कि मैंने इसे टीवी पर देखा और अखबारों में इसके बारे में पढ़ा लेकिन यह मेरी जानकारी में नहीं आया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। शराब घोटाला एक साल से चल रहा है, उन्होंने तब मुझ पर कार्रवाई क्यों नहीं की? स्थानीय निकाय चुनाव नजदीक आ रहे हैं और इसलिए वे मुझे बदनाम करना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं।

कवासी लखमा की गिरफ्तारी राजनीतिक षड़यंत्र: दीपक बैज

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ आदिवासी नेता कवासी लखमा की गिरफ्तारी ईडी द्वारा राजनैतिक साजिश है। सर्वविदित है कि अब देश में सीबीआई, आईटी, ईडी कार्यवाही क्यों करती है? जब-जब भाजपा के राजनैतिक एजेंडे को पूरा करना होता है जहां भी छोटा, बड़ा चुनाव हो वहां विपक्षी दलों के नेताओं को बदनाम करने के लिये ईडी कार्यवाही करती है। छत्तीसगढ़ में पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव है। ऐसे में ईडी भाजपा के इशारे में काम कर रही है। भाजपा चुनाव को टालने में लगी हुयी है। चुनाव कराना भाजपा की मजबूरी है, तो अब विपक्ष को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। कवासी लखमा की गिरफ्तारी ईडी, भाजपा के राजनैतिक एजेंडे को पूरा करने के लिये की है।

पवार मोदी को बुला रहे हैं, इंडि ब्लॉक में सब ठीक तो है!

नईदिल्ली। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र में इंडिया ब्लॉक टूटने की कगार पर नजर आ रहा है। शरद पवार ने साफ कर दिया था कि ये अलायंस तो लोकसभा चुनाव के लिए बना था और लोकल इलेक्शन को लेकर इसमें कोई बात नहीं हुई थी। अगर स्थानीय निकाय के चुनाव सभी पार्टियां अलग अलग लड़ें तो कोई हैरानी की बात नहीं है। इसमें पहले उद्धव ठाकरे ने लोकल बॉडी इलेक्शन अकेले लड़ने का ऐलान किया है। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने गठबंधन को लेकर बड़ा बयान देते हुए कह दिया कि अगर उसके सहयोगियों के बीच बातचीत बंद हो जाती है तो कोई भी गठबंधन सफल नहीं हो सकता। यानी महाविकास अघाड़ी इन दिनों एकला चलो रे की राह पर चल रही है। वहीं अब खबर है कि शरद पवार ने पीएम मोदी को आमंत्रण भेजा है।

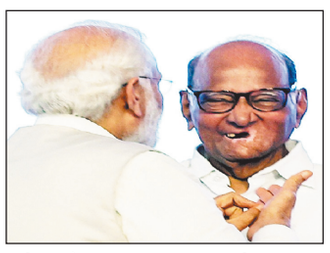

राकांपा (सपा) प्रमुख शरद पवार के निमंत्रण के बाद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी मराठी साहित्य महोत्सव, अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। यह घटनाक्रम इंडिया ब्लॉक के सदस्यों के बीच दरार के बीच आया है, जो शिवसेना (यूबीटी) द्वारा महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ने के अपने फैसले की घोषणा के बाद शुरू हुई थी। इससे पहले दिसंबर 2024 में शरद पवार ने दो किसानों के साथ पीएम मोदी से मुलाकात की थी और उन्हें महाराष्ट्र के अनार तोहफे में दिए थे। सूत्रों के मुताबिक, उस बैठक में प्रधानमंत्री को पवार की ओर से औपचारिक निमंत्रण दिया गया था। 98वां मराठी साहित्य सम्मेलन 21 से 23 फरवरी, 2025 के बीच दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित होने वाला है। प्रमुख मराठी साहित्यिक कार्यक्रम के उद्घाटन के इस निमंत्रण को अनिवार्य रूप से मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए केंद्र के प्रति आभार व्यक्त करने के संकेत के रूप में देखा गया था। सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री को अपने निमंत्रण में, पवार ने कहा था कि यह पहली बार है कि सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है और याद दिलाया कि कार्यक्रम के 37 वें संस्करण का उद्घाटन पूर्व प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था।

सीएम साय ने उपराष्ट्रपति का किया आत्मीय स्वागत

रायपुर । उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ गुरूघासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर के दीक्षांत समारोह में शामिल होने आज बिलासपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर में निर्मित हेलीपेड पर उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ का आत्मीय स्वागत किया।

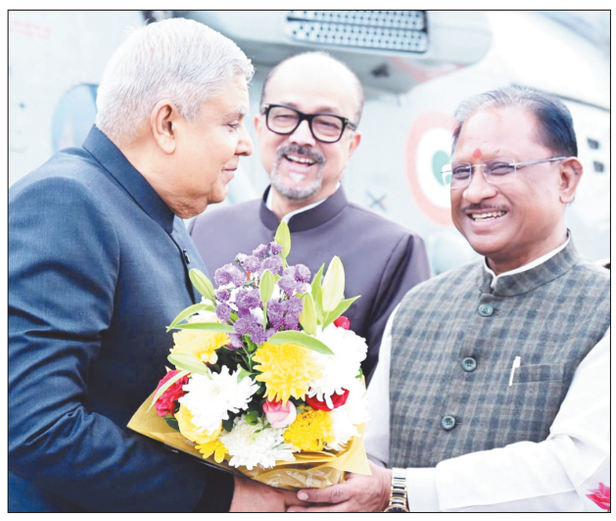

प्रमुख समाचार

भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन क्षेत्र में वाल्मिकी कॉलोनी में जूते बांटकर आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का उल्लंघन करने के आरोप में नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। घटना के संबंध में चुनाव

आयोग द्वारा मंदिर मार्ग स.।ह को लिखे गए पत्र के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर ने 15 जनवरी को स.।ह को एक पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने कहा कि शिकायत में दो कथित वीडियो साझा किए गए थे, जिसमें वर्मा को निर्वाचन क्षेत्र की महिलाओं को जूते बांटते देखा जा सकता है। शिकायत के आधार पर, आरओ ने एसएचओ को जांच शुरू करने और प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। प्रवेश वर्मा नई दिल्ली सीट से आप के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। नई दिल्ली विधानसभा सीट त्रिपक्षीय मुकाबले के लिए तैयार है क्योंकि कांग्रेस ने दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे और पार्टी के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा है।

मूर्तियों के मामले में मायावती को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

नई दिल्ली। बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) की प्रमुख मायावती को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट बड़ी राहत मिली। शीर्ष कोर्ट ने 2009 में उनकी सरकार में लगाई गई मूर्तियों पर जांच की मांग करने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया। याचिका में आरोप लगाया

गया था कि मायावती ने मुख्यमंत्री रहते हुए बजट से 2,000 करोड़ रुपये खर्च किए, जो उनके और उनकी पार्टी के चुनावी प्रतीक हाथी की मूर्तियों को स्थापित करने में खर्च किए गए थे। याचिका दो वकीलों रवि कांत और सुकुमार की ओर से दायर की गई थी। जस्टिस बी.वी.नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि अधिकांश मुद्दे अब अधिकतर मुद्दे अब अप्रासंगिक हो चुके हैं। कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि चुनाव आयोग पहले ही इस मुद्दे पर दिशा-निर्देश जारी कर चुका है। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया था कि 2008-09 और 2009-10 के दौरान जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थीं, तब राज्य के बजट से 2,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।

अमित शाह ने जवाहरलाल नेहरू पर लगाया बड़ा आरोप

कलोल। गृहमंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर की स्थितियों में सुधार हुआ है। उन्होंने बुधवार को गांधीनगर जिले के कलोल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज कश्मीर में श्रीनगर के लाल चौक से कृष्ण जन्माष्टमी शोभायात्रा के

गुजरने के दौरान कोई भी शरारत करने की हिम्मत नहीं करता। इस दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर भी तंज कसे। उन्होंने कहा कि वह पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू किया था। इसके तहत उन्होंने इस क्षेत्र को विशेष दर्जा दिया गया था। इस दौरान शाह ने मोदी सरकार की उपल्बिधयां भी गिनाईं। उन्होंने कहा, 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारतीयों के लिए भारत के स्वाभिमान और उसके सम्मान से बड़ा कुछ नहीं है। गृहमंत्री शाह ने कहा कि एक समय था जब श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए सेना की मदद की जरूरत होती थी। लेकिन आज, जब कृष्ण जन्माष्टमी की शोभायात्रा चौक से गुजरती है तो कोई भी शरारत करने की हिम्मत नहीं करता।

अमृतपाल सिंह की बनाई नई पार्टी, पिता ने किया लॉन्च

नई दिल्ली। पंजाब में राजनीतिक परिदृश्य में एक नए खिलाड़ी अकाली दल (वारिस पंजाब दे) ने एंट्री ले ली है। इस पार्टी का नेतृत्व खालिस्तान समर्थक नेता और खडूर साहिब से संसद सदस्य अमृतपाल सिंह कर रहे हैं। इसकी औपचारिक

घोषणा मुक्तसर के माघी मेले में की गई। पार्टी का लक्ष्य पंथिक क्षेत्र पर कब्ज़ा करना है जहां कभी शिरोमणि अकाली दल का दबदबा था, जो अब अस्तित्व के संकट का सामना कर रहा है। नए राजनीतिक दल का ऐलान अमृतपाल के पिता तरसेम सिंह, सासद सरबजीत सिंह खालसा और अन्य नेताओं ने किया। नया अध्यक्ष चुने जाने तक पार्टी को चलाने के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया है. सदस्य तरसेम सिंह, सर्बजीत खालसा, अमरदीप सिंह, हरभजन सिंह और सुरजीत सिंह हैं। इसमें पार्टी के संविधान, एजेंडा, नीति और अनुशासन को तय करने के लिए एक पैनल के गठन की घोषणा की गई। यह पैनल कार्यकारी समिति को पार्टी के संगठनात्मक ढांचे और उसकी गतिविधियों के संचालन पर सलाह देगा।

भ्रामक विज्ञापनों पर कार्रवाई में फेल राज्यों को सुप्रीम फटकार

नई दिल्ली। भ्रामक विज्ञापनों और चिकित्सा दावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। शीर्ष कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापनों और चिकित्सा दावों के खिलाफ कार्रवाई में फेल साबित होने वाले राज्यों को शीर्ष कोर्ट ने फटकार लगाई है। साथ ही ऐसे राज्यों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की

चेतावनी भी दी है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) के पूर्व अध्यक्ष आरवी अशोकन को बड़ी राहत भी दी है। अदालत ने साक्षात्कार में शीर्ष अदालत पर टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ शुरू की गई अवमानना कार्यवाही को बंद कर दिया है। पीठ ने पूर्व आईएमए अध्यक्ष के हलफनामे के साथ दी गई माफी को स्वीकार कर लिया और निर्णय लिया कि आगे कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं है। जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा, हम यह स्पष्ट करते हैं कि किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की ओर से गैर-अनुपालन पाए जाने पर संबंधित राज्यों के खिलाफ अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत कार्यवाही शुरू करनी पड़ सकती है।

हजार किलोमीटर दूर से संगम में लगा रहे ऑनलाइन डुबकी

महाकुंभ नगर (प्रयागराज)। वसुधैव कुटुम्बकम यानी पूरा विश्व एक (मेरा) परिवार है। इस धेय वाक्य को प्रयागराज का महाकुंभ मेला चरितार्थ कर रहा है। प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत के साथ ही करोड़ों सनातनी और श्रद्धालुओं का संगम की रेती पर पहुंचना शुरू हो चुका है। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी हजारों की संख्या में विदेशी मेहमान महाकुंभ के पावन मौके पर हिंदुत्व और सनातन को नमन करने प्रयागराज पहुंच रहे हैं। केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में महाकुंभ की धूम है। दुनिया में महाकुंभ की धूम की साक्षी वहां से आए दिन आ रही तस्वीरें हैं। अमेरिका, रूस, ब्राजील, स्पेन, जर्मनी, ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका ये तमाम वो देशों के नाम हैं। इसमें कई तुर्की, ईरान जैसे मुस्लिम बहुल देश भी शामिल हैं। जहां से लोग सनातन के समागम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। तमाम लोग प्रयागराज में महाकुंभ के विहंगम तस्वीरों को देखकर एकदम हैरान हैं।

दीवाने हुए पाकिस्तानी

भारत की कोई बड़ी खबर हो और उसमें पाकिस्तान का जिक्र न हो ऐसा शायद ही होता है। कुंभ के मामले में भी यही हुआ है।

प्रयागराज महाकुंभ को पाकिस्तान में भी देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि सीमा पार कुंभ का फर्स्ट डे फर्स्ट शो हिट हो गया है। पाकिस्तानी कुंभ को देख रहे हैं। उसके बारे में इतना सर्च कर रहे हैं कि इस बार पाकिस्तान में कुंभ को लेकर कई रिकॉर्ड टूट गए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि सनातन के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन को लेकर पाकिस्तानी इतने दीवाने क्यों हो गए? कहा जा रहा है कि पाकिस्तानियों ने हजार किलोमीटर दूर से संगम में ऑनलाइन डुबकी लगा ली है। महाकुंभ की शुरुआती तस्वीरें देख कर पाकिस्तानी झूम रहे हैं। सीमा पार बैठे लोगों के हैरान होने की वजह कुंभ में करोड़ों लोगों के आने की खबर है। महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा लोगों के शामिल होने का अनुमान है। इतने करोड़ लोगों का आंकड़ा पाकिस्तानियों की सोच से भी बड़ा है।

मुस्लिम देशों में भी यही हाल

महाकुंभ में 45 करोड़ लोगों के आने की बात पाकिस्तान को चौंका रही है। हर कोई ये आंकड़ा दोहरा रहा है। असल में पाकिस्तान की कुल आबादी 24 करोड़ के करीब है। जबकि महाकुंभ में केवल डेढ़ महीने में ही 45 करोड़ से ज्यादा लोग संगम तट पर पहुंचेंगे। यानी संगम के तट पर दो पाकिस्तान के बराबर लोग आएंगे। महाकुंभ के इन आंकड़ों के सामने में पूरा पाकिस्तान छोटा नजर आ रहा है। पाकिस्तानी सिर्फ श्रद्धालु ही नहीं कुंभ में शामिल होने वाले साधु संतों के बारे में जानकर भी आश्चर्य में हैं। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों ने कुंभ के बारे में इतनी जानकारी सर्च की कि एक नया रिकॉर्ड बन गया। गूगल ट्रेड के अनुसार पाकिस्तानियों ने कुंभ शुरू होने से चार दिन पहले 9 जनवरी को ही सर्च करना शुरू कर दिया था। 9 जनवरी को दोपहर साढ़े तीन बजे सबसे ज्यादा पाकिस्तानी कुंभ के बारे में सर्च कर रहे थे। पाकिस्तान अकेला नहीं है। दुनिया के दूसरे मुस्लिम देशों में भी यही हाल है। सऊदी अरब में बीते दिन सुबह 10 बजे के करीब टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक महाकुंभ ही रहा। 11 जनवरी को यूएस में सुबह के वक्त कुंभ सबसे ज्यादा ट्रेंड करने लगा। कतर और बहरीन जैसे मुस्लिमों देशों में भी कुंभ को लेकर यही दीवानगी दिखी। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तानियों के साथ पूरी दुनिया ये जानती है कि इससे बड़ा मेला पूरी धरती पर कहीं नहीं लगता है।

एप्पल को-फाउंडर की पत्नी ने ली दीक्षा

एप्पल के को फाउंडर और अरबपति कारोबारी स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल जॉब्स महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए पहुंचीं हैं। वह निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरि के शिविर में प्रवास कर रही हैं। जॉब्स 13 जनवरी को प्रयागराज पहुंची थीं। मकर संक्रांति पर स्नान करने की भी उनकी इच्छा थी, लेकिन तबीयत खराब हो जाने के कारण वह अमृत स्नान नहीं कर सकीं। बुधवार को उन्होंने अपने गुरु आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरि से दीक्षा ली। लॉरेन पॉवेल को महाकाली के बीज मंत्र की दीक्षा दी गई है। वह ? क्रीं महाकालिका नमः का जाप करेंगी। महाकुंभ में भारी भीड़ से अभिभूत एप्पल के सह-संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी प्रयागराज पहुंचने के बाद अस्वस्थ हो गई थी। उनका स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ हो गया था, लेकिन गंगा स्नान और आराम के बाद उनकी हालत में सुधार हो रहा है। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरि ने बताया कि सभी प्रश्न सनातन धर्म के इर्द-गिर्द घूमते हैं और उन्हें उत्तरों में बहुत खुशी और संतुष्टि मिलती हैं। लॉरेन की आध्यात्मिकता की खोज उन्हें महाकुंभ में ले आईं।

गंगालूर में आदिवासी के निर्माणाधीन घर पर चला बुलडोजर

बीजापुर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिला की संवेदनशील ग्राम पंचायत गंगालूर है। यहां सोमवार सुबह गंगालूर तहसीलदार ने अतिक्रमण की कार्रवाई की। टोंडापारा गंगालूर के निवासी सोमलु के निर्माणाधीन घर को जेसीबी के जरिए तोड़ दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान वहां कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही इस कार्रवाई की जानकारी लगी तो ग्रामीण आक्रोशित हो गए।

सभी गांव वालों ने पंचायत बैठक कर चक्काजाम कर विरोध करने का निर्णय लिया। चक्काजाम में जिला पंचायत सदस्य पुष्पा राव, सरपंच राजू कलमू, उपसरपंच समेत सैकड़ों की संख्या में ग्राम वासी शामिल हुए। मंगलवार बाजार के दिन सुबह 7 बजे से गंगालूर 22 पारा के सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण इकट्ठा होकर जिला प्रशासन और तहसीलदार के विरोध में नारे लगाने लगे। सोमलु को मुआवजा, जमीन और घर की मांग करने लगे।

गंगालूर के ग्रामीणों के समर्थन में भाजपा पूर्व अध्यक्ष बस्तर जिला प्रभारी जी वेंकट, नवनिर्वाचित भाजपा जिलाध्यक्ष घासीराम नाग,

पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष सुखलाल पुजारी रोड में बैठ गए और ग्रामीणों का साथ दिया। उन्होंने अधिकारियों को अपनी मनमानी से बाज आने की नसीहत तक दी।

ग्रामीण ने कहा मेरा घर जबरदस्ती तोड़ा गया इसलिए यहां अनशन किया गया। जनदर्शन में भी मैंने गुहार लगाया है। अब मुआवजा देने का आश्वासन दिया गया है। मांग पूरी नहीं होगी तो फिर बीजापुर में प्रदर्शन करेंगे।

सरपंच राजू ने कहा खुद की जमीन पर सोमलू मकान बना रहे थे। कोई नोटिस नहीं दिया गया। हम देवगुड़ी की मीटिंग कर रहे थे, तभी अचानक पता चला कि बुलडोजर चल रहा है। हमने अधिकारियों को फोन किया लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। ग्राम सभा में सोमलू को 2 डिसमिल जमीन का आवेदन आया था, प्रस्ताव पारित कर तहसील ऑफिस में जमा किया गया था। जनदर्शन में भी गए थे। सभी नेता, विधायक, मंत्री को भी आवेदन दिया गया है। लेकिन मनमानी कर बुलडोजर चला दिया।

मंगलवार बाजार होने से गंगालूर के कोवापारा चौक में धरना से गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। बाजार व्यापारी ने भी कुछ देर गांव के रोड में बैठ ग्रामीणों का समर्थन किया। आखिरकार जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने ग्रामीणों के साथ बैठक कर निराकरण का आश्वासन दिया। फिर ग्रामीण माने और प्रदर्शन रोका गया।

सटोरियों का मुख्य सरगना गिरफ्तार

सरगुजा। रेड के दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार हुए सटोरियों के मुख्य सरगना सुधीर गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा कि सटोरियों का तार महादेव सट्टा एप से जुड़ा है। सटोरियों ने करीब 15 बैंकों में सैकड़ों खाते खुलवा रखे थे। अब तक पुलिस सौ करोड़ से ऊपर की लेन-देन होने का खुलासा कर चुकी है।

बता दें कि सटोरिए सरगुजा में एक कमरे को ऑफिस बनाकर सट्टा खिलवा रहे थे। इसकी सूचना मिलने पर हाल ही में पुलिस ने उनके घर में छापा मारा, जहां 4 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं सुधीर गुप्ता फरार होने में कामयाब हो गया था। मौके से पुलिस ने बड़ी मात्रा में बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, मोबाइल, टीवी, क्यूआर कोड, नगद रकम, हवाला के पैसों में उपयोग होने वाले नोट सहित अन्य सामान पुलिस ने बरामद किया था। एसपी के निर्देश पर सीएसपी के नेतृत्व में पुलिस ने मुख्य सरगना सुधीर गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है।

नारायणपुर में 32 लाख के चार इनामी नक्सलियों का सरेंडर

नारायणपुर। हिंसा की 40 से अधिक घटनाओं में शामिल और 32 लाख रुपये के सामूहिक इनाम वाले चार नक्सलियों ने बुधवार को छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में आत्मसमर्पण कर दिया। नारायणपुर एसपी प्रभात कुमार ने कहा कि एक जोड़े सहित कैडरों ने खोखली और अमानवीय माओवादी विचारधारा और वरिष्ठ कैडरों द्वारा निर्दोष आदिवासियों के शोषण से निराशा का हवाला देते हुए यहां वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।

नारायणपुर एसपी ने कहा कि वे जिला पुलिस द्वारा शुरू किए गए निया पुलिस निया नार (हमारा गांव, हमारी पुलिस) आत्मसमर्पण और पुनर्वास अभियान से भी प्रभावित हुए। इन चार कैडरों में से गांधी ताती उर्फ अरब उर्फ कमलेश (35) और मैनू उर्फ हेमलाल कोर्राम (35) माओवादियों की डिविजनल कमेटी के सदस्य थे। प्रभात कुमार ने कहा कि पड़ोसी बीजापुर जिले के निवासी कमलेश ने माओवादियों के माड़ डिवीजन और नेलनार क्षेत्र समिति में विभिन्न पदों पर काम किया था और आठ साल तक नारायणपुर के नेलनार इलाके में 50 से अधिक गांवों में आतंक का राज कायम किया था। वह 2010 में तत्कालीन दंतेवाड़ा जिले (अब सुकमा में स्थित) में ताड़मेटला नरसंहार में कथित रूप से शामिल था, जिसमें 76 सुरक्षाकर्मियों की जान चली

गई थी। पुलिस अधिकारी ने कहा कि हेमलाल, जो माओवादियों की आमदई क्षेत्र समिति के सचिव के रूप में सक्रिय था, कथित तौर पर बुकिनटोर आईईडी विस्फोट घटना में शामिल था, जिसमें 2021 में पांच जवान मारे गए थे। आत्मसमर्पण करने वाले दो अन्य कैडरों की पहचान रंजीत लेकामी उर्फ अर्जुन (30) और उसकी पत्नी कोसी उर्फ काजल (28) के रूप में हुई है। एसपी ने कहा कि चारों के सिर पर 8-8 लाख रुपये का इनाम था और वे हिंसा की 40 से अधिक घटनाओं में शामिल थे। पुलिस अधिकारी ने कहा, उनके आत्मसमर्पण करने के फैसले से माओवादियों की नेलनार और आमदई क्षेत्र समितियों को बड़ा झटका लगा है, जो अतीत में हिंसा की कई घटनाओं को अंजाम देने में सहायक रहे थे। उन्होंने कहा कि उन सभी को 25,000 रुपये की सहायता प्रदान की गई और सरकार की नीति के अनुसार उनका पुनर्वास किया जाएगा।

तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी

जीपीएम से 992 बोरी धान जब्त, मचा हड़कंप

गौरेला पेंड्रा मरवाही। समर्थन मूल्य पर छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को अब 15 दिन शेष बचे हैं। ऐसे में बिचौलिये और धान तस्कर फिर सक्रिय हो गए है। मध्यप्रदेश से लाए गए धान को किसानों के पट्टे में बेचने का लगातार प्रयास जारी है। एक बार स्थानीय प्रशासन के द्वारा छापेमारी की कार्यवाही करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में दबिश देकर चार जगहों से 992 बोरी अवैध धान जब्त की गई। ये पूरी कार्रवाई मरवाही एसडीएम के नेतृत्व में की गई।

छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी के लिए अभी महज कुछ ही दिन बचे हुए हैं। ऐसे में धान तस्कर रात के अंधेरे में मध्य प्रदेश से धान लाकर छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवो में ला रहे है, जो बाद में किसानों के पट्टे में खरीदी केंद्रों में खपाया जाता है। ऐसे में एक बार फिर स्थानीय प्रशासन ताबड़तोड़ छापेमारी कर रहा है।

मरवाही एसडीएम प्रफ्फुल रजक के नेतृत्व में तहसील दार मरवाही प्रीति शर्मा व राजस्व अमले ने चार जगहों पर छापेमारी करते हुए 992 बोरी धान को बिचैलियों द्वारा रखे गए गोदामों और किसानों के घरों से जब्त किया।

जिसमें राजकुमार गुप्ता अज्जू निवासी धनपुर से 600 बोरी 240 क्विंटल, रविकांत पांडेय के गोदाम से 141 बोरी 56 क्विंटल धान, ओम गुप्ता निवासी सिवनी गांव से 141 बोरी 56 क्विंटल, प्रेम कुमार यादव बदरौडी ग्राम के देवगवा से 110 बोरी 44 क्विंटल, कुल 992 बोरी धान जिसकी मात्रा 396 क्विंटल धान को प्रशासन के द्वारा जब्त की है। वहीं सिवनी निवासी ओम गुप्ता का गोदाम को भी प्रशासन के द्वारा सील कर दिया गया। जिससे एक बार फिर सीमावर्ती क्षेत्र में धान को मध्यप्रदेश से लाकर छत्तीसगढ़ में खपाने वाले बिचैलियों में हड़कंप मचा हुआ है।

कुसुम प्लांट हादसा, 6 सदस्यीय जांच टीम का गठन

15 दिनों के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश

मुंगेली। सरगांव के रामबोड़ स्थित कुसुम स्टील प्लांट हादसे के मामले की जांच में तेजी लाने के लिए विशेष टीम का गठन कर दिया गया है। एसपी भोजराम पटेल ने मामले की विस्तृत जांच के लिए 6 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया है। जांच टीम का पर्यवेक्षण डीएसपी नवनीत पाटिल करेंगे। वहीं टीआई संतोष शर्मा को जांच टीम का प्रभारी बनाया गया है। टीम को 15 दिनों के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया गया है। टीम को अन्य सभी कार्यों से मुक्त रखा गया है। हादसे की सभी पहलुओं से विस्तृत और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाएगी।

बता दें कि कुसुम स्मेल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड पॉवर प्लांट में 4 मजदूर साइलो टैंक की चपेट में आने से नीचे दब गए। मौके पर एक मजदूर मनोज कुमार धृतलहरे का रेस्क्यू कर उसे इलाज के लिए बिलासपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। वहीं भारी साइलो को हटाने के बाद मलबे के नीचे दबे तीन लोगों के शव बरामद किया गया। शवों की पहचान इंजीनियर बिलासपुर के सरकंडा निवासी जयंत साहू पिता काशीनाथ साहू के अलावा दो मजदूर ङ्क जांजगीर-चांपा जिला के तागा निवासी अवधेश कश्यप पिता निखादराम कश्यप और बलौदाबाजार जिले के अकोली निवासी प्रकाश यादव पिता परदेशी यादव के रूप में हुई थी।

देर रात डिप्टी सीएम को लेनी पड़ गई बच्चों से मदद

■ इसके बाद पहुंचे कार्यक्रम स्थल

कबीरधाम। कबीरधाम जिले से कवर्धा विधायक व डिप्टी सीएम विजय शर्मा यहां के दौरे पर हैं। बीती मंगलवार देर रात तक वे कई कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान एक ऐसा भी वाक्या हुआ कि देर रात डिप्टी सीएम विजय शर्मा को बच्चों से मदद लेनी पड़ गई। इसके बाद वे कार्यक्रम स्थल पहुंच सके। दरअसल, वे सहसपुर लोहारा ब्लॉक के विभिन्न गांव में दौरे पर गए थे। इसी दौरान ग्राम धनौरा में उनका काफिला अचानक रुका, आसपास मौजूद बच्चों से उन्होंने कार्यक्रम स्थल के बारे में पूछा। फिर बच्चों को अपने वाहन में ही बैठाकर कार्यक्रम स्थल पहुंच सके।

डिप्टी सीएम विजय शर्मा के गोद में एक बच्चा बैठा था, जो आगे का रास्ता दिखा रहा था। वही कार्यक्रम में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इस गांव में 41.65 लाख के विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन किया है। इसी प्रकार वे जिले के विभिन्न ग्रामों में

आयोजित मां शाकंभरी जयंती के कार्यक्रमों में शामिल हुए। ग्राम भौंदा, तरेगांव मैदान में आयोजित आयोजनों में उन्होंने मां अन्नपूर्णा के अवतार मां शाकंभरी की पूजा-अर्चना कर प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश की साय सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना है। ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जा रहा है और सभी बुनियादी सुविधाओं में सुधार लाया जा रहा है।

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इस दौरान लोगों से सीधा संवाद किया। उनकी मांग, समस्या और शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुना और उनके अनेक मांगों को तत्काल पूरा करते हुए विकास कार्यों की घोषणा भी की। ग्राम भौंदा में महतारी सदन और मांदी घाट से भौंदा तक सड़क निर्माण की घोषणा की। साथ ही ग्राम तरेगांव मैदान में महतारी सदन व 13 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन निर्माण की घोषणा की। श्री शर्मा ने कहा कि गांव के महिलाओं को महतारी वंदन और बुजुर्गों एवं दिव्यांगों को पेंशन की राशि पंचायत में ही मिलेगी।

इस नई व्यवस्था के तहत महिलाओं को बैंक जाकर पैसे निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। वे बैंक सखी या सीएससी के माध्यम से अपने गांव में ही राशि प्राप्त कर सकेंगी। इसके लिए कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर ग्राम पंचायत के पास भवन निर्माण और शेड लगाने की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए। विजय शर्मा ने पटेल (मरार) समाज द्वारा आयोजित मां शाकंभरी जयंती के आयोजन के लिए समाज के सभी प्रमुखों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मां शाकंभरी, मां अन्नपूर्णा और शक्ति स्वरूपा दुर्गा का अवतार हैं।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

क्राइम किलर शशिमोहन सिंह का एसएसपी प्रमोशन

जशपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर के एसपी शशिमोहन सिंह को एसएसपी के पद पर पदोन्नत होने के अवसर पर बैच और स्टार पहनाकर बधाई दी। दरअसल, यह आयोजन बगिया स्थित मुख्यमंत्री के निजी निवास पर बीती रात 11 बजे पीपींग सेरेमनी के तहत संपन्न हुआ। कार्यक्रम में कमिश्नर नरेन्द्र सिंह दुग्गा, आईजी अंकित गर्ग, कलेक्टर रोहित व्यास, जिला पंचायत सीईओ अभिषेक कुमार और पत्नी रेखा सिंह व बेटे रिभु समर्थ सिंह भी उपस्थित थे। शशिमोहन सिंह 1997 बैच के डीएसपी रहे हैं। 2012 में उन्हें आईपीएस अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था। पिछले एक वर्ष से वे जशपुर में पुलिस अधीक्षक के रूप में सेवा दे रहे हैं।

रविकांत मिश्रा गिरफ्तार एक आरोपी फरार

दुर्ग/भिलाई। दुर्ग जिले में लंबे समय से फरार आरोपी रविकांत मिश्रा और गोविंदा चौहान में से पुलिस ने रविकांत मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। गोविंदा चौहान की तलाश की जा रही है। पुलिस रविकांत को रिमांड में लेकर आगे की पूछताछ करेगी। सुपेला थाना पुलिस के मुताबिक रविकांत मिश्रा और गोविंदा चौहान के खिलाफ सितंबर 2024 में मामला दर्ज किया गया था। तब से दोनों आरोपी फरार थे। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली थी कि रविकांत मिश्रा और गोविंदा चौहान दोनों भिलाई में ही छिपकर रह रहे हैं। इतना ही नहीं रवि मिश्रा ने फरारी के दौरान ही एक लड़की से सगाई तक कर ली है। इसके बाद पुलिस एक्टिव हुई। मंगलवार देर रात सुपेला पुलिस की एक टीम रविकांत मिश्रा के फ्लैट में पहुंची और उसे वहां से गिरफ्तार कर थाने लाई। पुलिस अभी इस गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रही है। सूत्रों के मुताबिक रविकांत मिश्रा को कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिर पुलिस रविकांत मिश्रा से पूछताछ करेगी कि ऑनलाइन सट्टा चलाने के लिए उसने आईडी कहां से लाया।

बलौदाबाजार में नौकरी लगाने महिला से ठगे लाखों रुपए

बलौदाबाजार। नौकरी की तलाश में बलौदा बाजार की एक महिला ने ठगी का शिकार हो गई। जब एक आरोपी ने उसे पटवारी की नौकरी दिलाने का झांसा दिया और इसके बदले में उससे लाखों रुपए ठग लिए। जब महिला का चयन नहीं हुआ, तो आरोपी ने उसे फर्जी नियुक्ति पत्र थमा दिया। यह मामला बलौदाबाजार जिले के सुहेला क्षेत्र की रहने वाली 34 वर्षीय पूर्णिमा ध्रुव का है। पूर्णिमा ने अपने सुनहरे भविष्य की उम्मीद में एक व्यक्ति पर विश्वास किया था। आरोपी ने उसे पटवारी की नौकरी दिलाने का वादा किया। आरोपी दुर्ग जिले के छावनी थाना क्षेत्र के भिलाई प्रगति नगर कैंप 1 का रहने वाला है। आरोपी का नाम संतोष सिंह राजपूत उर्फ दीपक है। संतोष ने महिला से पटवारी की नौकरी दिलाने के नाम पर कुल 6 ।30 लाख रुपए की रकम ले ली। पूर्णिमा का चयन जब पटवारी की नौकरी के लिए नहीं हुआ, तो आरोपी संतोष ने उसे एक फर्जी नियुक्ति पत्र थमा दिया। यह नियुक्ति पत्र भारत सरकार के निर्वाचन आयोग का था, जो पूरी तरह से नकली था।

नाबालिगों को नशे के दलदल में धकेलने वाला गिरफ्तार

कबीरधाम। कबीरधाम पुलिस ने नाबालिग बच्चों को नशे की लत में धकेलने वाले ओमंग देवांगन को गिरफ्तार किया। आरोपी जो अमर सायकल स्टोर, छोटे बाजार पिपरिया का संचालक है, बच्चों को साइकिल पंचर बनाने में उपयोग होने वाले सोल्यूशन को नशा करने के लिए ज्यादा कीमत पर बेचता था। यह सोल्यूशन एक हानिकारक पदार्थ है, जो बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है और उनके भविष्य को बर्बाद कर सकता है। एडिशनल एसपी पुष्पेंद्र बघेल ने बताया कि मुखबिर से सूचना प्राप्त होने के बाद, पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए एक सुनियोजित योजना बनाई। टीम ने एक को ग्राहक बनाकर आरोपी से संपर्क किया और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपी के पास से 202 नग सोल्यूशन ट्यूब बरामद की गई। पुलिस की इस कार्रवाई से यह साफ हो गया है कि नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए कबीरधाम पुलिस पूरी तरह प्रतिबद्ध है। गिरफ्तारी के दौरान, आरोपी ने पुलिस और गवाहों को धमकी देने का प्रयास किया।

जांजगीर-चांपा में गार्ड से 78.41 लाख की लूट

जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में बाइक सवार दो बदमाश गार्ड को गोली मारकर 78.41 रुपये लूटकर फरार हो गए। यह रकम शराब की दुकानों से कलेक्शन कर वैन में रखी गई थी। लूट के 10 घंटे बाद भी हमलावरों का सुराग नहीं, तलाश जारी है। पुलिस ने बताया कि यह वारदात शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के तहत आने वाले खोखरा गांव में शराब की दुकान के बाहर हुई। वैन में तीन लोग सवार थे, जो शराब की दुकानों से धन संग्रह कर खोखरा गांव की दुकान पर पहुंचे थे। कर्मचारी और ड्राइवर दोनों दुकान के अंदर चले गए और गार्ड वाहन के पास खड़ा था। अचानक बाइक से दो जवान पहुंचे और गार्ड के पैर में गोली मार दी और वाहन में रखे रुपये से भरे बैग को लेकर फरार हो गए। घायल गार्ड को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने नाकेबंदी कर बदमाशों को पकड़ने की कोशिश कर रही है।

कलेक्ट्रेट कार्यालय और एसपी निवास के पास दिखा तेंदुआ

■ वन विभाग के अधिकारियों में मचा हड़कंप

गरियाबंद। जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कलेक्ट्रेट कार्यालय और एसपी निवास के पास तेंदुआ देखा गया। इस घटना से वन विभाग के अधिकारी भी अलर्ट हो गए। मौके पर किसी तरह ड्यूटी में तैनात जवानों ने तेंदुआ को खदेड़ दिया। लेकिन इलाके के लोगों में अभी भी तेंदुआ का दहशत बना हुआ है।

दरअसल, गरीयबंद के सिविल लाइन स्थित एसपी के बंगले में देर रात एक तेंदुआ घुस गया। इस दौरान एसपी अपने बंगले में ही मौजूद थे। मौके पर तैनात जवानों ने किसी तरह से तेंदुए को खदेड़ दिया। इसकी सूचना के बाद वन विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। घटना के बाद से एसडीओ गरियाबंद रेंज अफसर, डिप्टी रेंजर सहित वनकर्मी लगातार एसपी निवास के आसपास

लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। बता दें कि एसपी निवास कलेक्ट्रेट कार्यालय के ठीक बगल में है। एडिशनल एस पी और एस।डी।ओ वन मनोज चंद्राकर ने इस घटना की पुष्टि की है।

वन विभाग तेंदुए के पगमार्क और दीवारों से कूद कर जाने के निशान का अध्ययन करने में जुटा हुआ है। तेंदुआ केशेडहर की ओर से पहुंच पुलिस अधीक्षक के निवास पर पहुंचा था। एसडीओ ने बताया कि करीब चार साल का तेंदुआ था, जो कूद कर के एसपी निवास में पहुंच गया, जिसके बाद वो जिला पंचायत ऑफिस चले गया। जिसके बाद हमने आसपास देखा कि तेंदुआ भाग तो नहीं गया है, तब तेंदुआ एसपी निवास के पीछे के हिस्से में कूदकर जंगल की तरफ भाग गया। गरियाबंद वन क्षेत्रों से घिरा हुआ है। कभी-कभी भोजन की ताश में तेंदुआ भटकते हुए आ जाता है। आज भी तेंदुआ सड़क पार कर के यहां आया था। लेकिन किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है।

गरियाबंद में तेंदुए के दहशत का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले तेंदुए को जिला अस्पताल के पास देखा गया था। आधी रात में तेंदुआ गरियाबंद के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाता है। तेंदुआ का दहशत इस कदर है कि साप्ताहिक बाजार लगने वाली जगह में वन कर्मी तैनात रहते है। वन विभाग सालभर से तेंदुए को पकड़ने की कोशिश में जुटा हुआ है। जिसके लिए पिंजरा भी मंगवाया गया था। लेकिन वन विभाग तेंदुए को पकड़ने में अबतक सफल नहीं हो पाया है।

छत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण कटौती मुद्दे पर कांग्रेस का हल्लाबोल

पुलिस कांग्रेसियों के बीच झूमाझटकी, भाजपा पर कटौती का आरोप

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण में हुई कटौती को लेकर कांग्रेस सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन कर रही है। बिलासपुर में भी कांग्रेस ने विरोध जताया। बिलासपुर कांग्रेस भवन से सिविल लाइन थाना गिरफ्तारी देने बड़ी संख्या में पहुंचे कांग्रेसियों को पुलिस ने बीच में ही रोक दिया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेसियों के बीच झूमाझटकी भी हुई।

जब पुलिस ग्राउंड के पास ही पुलिस ने कांग्रेसियों को रोका तो कांग्रेसी बीच सड़क में ही बैठ गए। कांग्रेस नेता और

कार्यकर्ताओं ने सीएम साय के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार ने साजिश कर ओबीसी आरक्षण में कटौती की है। जिला और जनपद पंचायतों में ओबीसी का आरक्षण ही खत्म कर दिया गया है।

नगरीय निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) वर्ग में भी भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। ओबीसी समाज ने आरक्षण के विरोध में पिछले दिनों बस्तर संभाग में महाबंद भी बुलाया था। पिछड़ा वर्ग समाज का कहना है कि सरकार द्वारा नगरीय निकाय चुनाव में जो आरक्षण तय किया गया है, उसे निरस्त किया जाए। दोबारा से आरक्षण कराकर ओबीसी समाज को आरक्षण का लाभ दिया जाए। ओबीसी समाज ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि पिछड़ा वर्ग समाज की मांगों पर सरकार ध्यान नहीं देगी तो उग्र आंदोलन करेंगे।

संक्षिप्त समाचार

नगरीय निकाय में ओबीसी को 30 प्रतिशत मिला है आरक्षण : अरुण साव

रायपुर। ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस आज प्रदेशभर में प्रदर्शन कर रही है। इस मामले में डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, नगरीय निकाय में ओबीसी को 30त्न आरक्षण मिला है। क्या कांग्रेस इसका भी विरोध कर रही है? साव ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर आरक्षण दिया गया है। भ्रम, भय और भ्रष्टाचार कांग्रेस के राजनीति का आधार रहा है। कांग्रेस इस तरह की राजनीति करना बंद करे। अरुण साव ने कहा, कांग्रेस के भ्रम की बातों में जनता नहीं आने वाली है। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को घेरते हुए उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने का आरोप लगाया। साव ने व्यक्तिगत टिप्पणी को निम्न स्तर की राजनीति बताते हुए कहा, निम्न स्तर की राजनीति से आहत हूं। ये सिर्फ मेरे वकालत पर प्रश्नचिन्ह नहीं उठा रहे। स्टेट बार कौंसिल जिन्होंने मुझे डिग्री दी उनका भी अपमान किया है। मेरे साथ सभी वकालत की डिग्रीधारियों का भी अपमान कर रहे हैं। विधानसभा में उनके सभी सवाल का मैंने जवाब दिया है।

रायगढ़, मुंगेली और बस्तर ग्रामीण के कांग्रेस ने बदले जिला अध्यक्ष

रायपुर। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को देखते हुए छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी ने रायगढ़, मुंगेली और बस्तर ग्रामीण के जिला अध्यक्षों को बदल दिया है। इन नियुक्तियों से पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलने की उम्मीद है। नागेश नेगी- रायगढ़, घनश्याम वर्मा- मुंगेली और परमेश्वर शुक्ला- बस्तर ग्रामीण शामिल है।

राकेश पुराम को मुख्य तकनीकी परीक्षक का अतिरिक्त प्रभार

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ लोक आयोग में तकनीकी सलाहकार के पद पर पदस्थ श्री राकेश पुराम को मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) कार्यालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राज्य शासन द्वारा जारी आदेश के तहत, श्री राकेश पुराम अपने वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) का कार्यभार भी अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संभालेंगे।

किसानों से अब तक 121 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से शुरू हुए

धान खरीदी का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। वहीं धान खरीदी व्यवस्था पर वरिष्ठ अधिकारियों का लगातार मॉनीटरिंग जारी है। राज्य में अब तक लगभग 121 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। धान खरीदी के एवज में 22.49 लाख किसानों को बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत 25 हजार 549 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। प्रदेश के समस्त पंजीकृत कृषकों को खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान विक्रय के लिए टोकन की सुविधा ऑनलाइन एप (टोकन तुंहर हांथ) एवं उपार्जन केन्द्रों में 25 जनवरी 2025 तक के लिए उपलब्ध कराया गया है। किसान सुविधा अनुसार तारीख का चयन कर नियमानुसार धान विक्रय कर सकते है। धान खरीदी के साथ-साथ मिलर्स द्वारा धान का उठाव भी तेजी से हो रहा है। अब तक 92.65 लाख मीटरिक टन धान के उठाव के लिए डीओ और टीओ जारी किया गया है, इसके एवज में 65 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव कर लिया गया है। इस खरीफ वर्ष के लिए 27.78 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। इसमें 1.59 लाख नए किसान शामिल है। इस वर्ष 2739 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है।

रेडक्रास सोसायटी के चेयरमैन बने राजू शर्मा, राज्य प्रतिनिधि बने डॉ. फरिश्ता

कलेक्टर की अध्यक्षता में रेडक्रास सोसायटी की प्रबंध समिति का गठन

रायपुर । कलेक्टर एवं रेडक्रास सोसायटी के अध्यक्ष डॉ. गौरव सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित जिला रेडक्रॉस सोसायटी की सामान्य सभा बैठक में 20 सदस्यीय प्रबंध समिति का गठन किया गया। बैठक में प्रबंध समिति के सदस्यों द्वारा सोसाइटी के पदाधिकारियों के चुनाव के लिए मतदान किया गया।

इस चुनाव में जिला पंचायत के सभापति राजू शर्मा ने अपने प्रतिद्वंदी सत्यनारायण पांडे को दो मतों से हराकर इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन के पद पर विजय प्राप्त की। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए डॉ. प्रीति नारायण ने श्रीमती मनी मुक्ता पाटील को 8 मतों से हराया। कोषाध्यक्ष पद के लिए श्रीमती पल्लवी पांडे ने मोहन सिंह छावड़ा को 8 मतों से पराजित किया। राज्य प्रतिनिधि के पद के लिए डॉ. ए फरिश्ता ने अवघड राजेश बाबा को 16 मतों से हराया। चुनाव परिणाम के बाद सभी विजयी प्रत्याशियों और प्रबंधन समिति के सदस्यों को कलेक्टर ने शपथ दिलाई। प्रबंध समिति के चयन के लिए कुल 51 मत पड़े, जिनमें से एक मत कारणवश निरस्त किया गया।

चुनाव में 29 सदस्य प्रबंध समिति के लिए दावेदार थे, जिनमें से 20 को चुना गया। कलेक्टर डॉ गौरव सिंह ने इस अवसर पर विजयी प्रत्याशियों को बधाई देते हुए कहा कि प्रबंध समिति के सदस्य सोसाइटी के विस्तार के लिए योजना बनाएं और हर सदस्य को कम से कम 10 लोगों को आजीवन सदस्यता दिलाने का कार्य करें। इसके अलावा संरक्षक सदस्य बनाने की दिशा में भी प्रयास करें। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप सहित सोसाइटी के सदस्य मौजूद थे।

पंचायत राज अधिनियम में संशोधन को हाईकोर्ट में चुनौती

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण का विवाद बढ़ता जा रहा है। प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार ने पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया है। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में जिला पंचायत सूरजपुर के उपाध्यक्ष नरेश रजवाड़े ने याचिका लगाई है। इस मामले पर हाईकोर्ट में जल्द सुनवाई हो सकती है।

सूरजपुर जिला पंचायत के उपाध्यक्ष नरेश रजवाड़े ने हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से ओबीसी आरक्षण शून्य किए जाने के खिलाफ याचिका दायर किया है। रजवाड़े ने मामले को लेकर हाइकोर्ट में अधिवक्ता शक्ति राज सिन्हा के माध्यम से याचिका पेश की है। याचिकाकर्ता के मुताबिक, पांचवी अनुसूची में शामिल जिलों में ओबीसी वर्ग को आरक्षण प्रदान करने वाली छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 129(ड।) की उपधारा (03) को लोप करने के लिए पिछले साल 3 दिसंबर को राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश -2024 को लाया। भारत के संविधान की अनुच्छेद 213 में निहित प्रावधान के तहत कोई भी अध्यादेश अधिकतम छह माह की अवधि तक ही क्रियाशील होता है अथवा विधानसभा के आगामी सत्र में अनिवार्य रूप से प्रस्ताव पारित कर अधिनियम का रूप दिलाना होता है, जिसमें छत्तीसगढ़ शासन ने गंभीर चूक की है। उक्त अध्यादेश जारी होने के बाद 16 से 20 जनवरी 2024 तक आयोजित छत्तीसगढ़ विधान सभा के आहूत सत्र में इस महत्वपूर्ण अध्यादेश को पारित नहीं कराते हुए मात्र विधानसभा के पटल पर रखा गया है, जिसके कारण उक्त अध्यादेश वर्तमान में विधिशून्य/औचित्यविहीन हो गया है। ऐसी स्थिति में वर्तमान में उक्त संशोधन के आधार पर छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम (5) में 24 दिसंबर 2024 को किया गया संशोधन पूर्णत: अवैधानिक हो गया है। हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका में कहा गया कि इस प्रकार अवैधानिक हो चुके संशोधित छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम (5) के आधार पर प्रदेश के संचालक पंचायत एवं सभी जिलों में कलेक्टर द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए जारी किया गया आरक्षण रोस्टर पूर्णत: अवैधानिक हो गया है। इसे निरस्त कर छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के पूर्व प्रावधान के आधार पर वैधानिक रूप से पंचायत चुनाव कराया जाए।

गणतंत्र दिवस पर राजभवन में होगा स्वागत समारोह

रायपुर। गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी 2025 को राज्यपाल श्री रमेन डेका की गरिमामय उपस्थिति में राजभवन में शाम 5:15 बजे से स्वागत समारोह का आयोजन किया जाएगा। जिसमे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, पद्मश्री, पद्मभूषण से सम्मानित राज्य के नागरिकों, जनप्रतिनिधियों सहित गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित किया जाएगा।राजभवन में गणतंत्र दिवस के अवसर पर संध्याकाल में एट होम फंक्शन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए आज राज्यपाल के सचिव श्री यशवंत कुमार ने विभिन्न विभागों की बैठक ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राजभवन परिसर एवं आस-पास की साफ-सफाई, स्वच्छ पेयजल, रोशनी एवं झालर व्यवस्था, ट्रैफिक, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, आमंत्रण पत्रों का मुद्रण एवं वितरण एवं अन्य व्यवस्था के संबंध में सभी आवश्यक निर्देश दिये गये। बैठक में रायपुर जिले के प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारी, राजभवन के अधिकारी, नगर निगम, लोकनिर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, बिजली, उद्यानिकी, आयुष विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

रायपुर नगर निगम में भाजपा का महापौर बनाने का लक्ष्य: मूणत

विधायक ने कार्यकर्ताओं को दिए जीत के टिप्स, रायपुर पश्चिम क्षेत्र के पूरे 20 वार्ड की बैठक संपन्न

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी नगरी निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर जोर-जोर से जुड़ चुकी है। संगठन के विभिन्न स्तरों में लगातार बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में पिछले एक सप्ताह में लगातार रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के पूरे 20 वार्ड की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक की अध्यक्षता पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक श्री राजेश मूणत ने की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए निर्देशित किया और संगठन की रणनीति से अवगत कराया।

बैठक में भाजपा विधायक राजेश मूणत ने कहा कि पार्टी ने सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में जीत दर्ज करने का लक्ष्य तय किया है। उन्होंने कहा कि रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के सभी वार्डो में पार्टी जिस भी प्रत्याशी को टिकट देगी, हमें संगठित होकर उस प्रत्याशी को विजयी बनाना है। विधानसभा और लोकसभा के साथ ही उपचुनाव

में जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भाजपा का परचम लहराया है, वैसे ही आगामी चुनाव में भी भाजपा को जीताना है। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को कमर कसनी होगी। उन्हें भाजपा के एक साल के कार्यकाल को लेकर जनता के बीच जाना है। ऐसे में जनता को अपने पक्ष में लाने की कोशिश सभी कार्यकर्ताओं को करनी होगी। सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचाना है। इसके साथ ही वार्ड स्तर पर बैठक के साथ कार्यकर्ताओं को घर-घर जाकर इन योजनाओं से जनता को रूबरू कराना होगा।

भाजपा विधायक श्री राजेश मूणत ने कार्यकर्ताओं से कहा कि भाजपा का लक्ष्य रायपुर नगर निगम में अपना महापौर बनाना है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और कार्यों का लाभ चुनाव में मिलेगा। जबकि कांग्रेस को राज्य में भूपेश बघेल और रायपुर में महापौर एजाज ढेबर के कार्यकाल में हुए बड़े घोटालों का नुकसान उठाना पड़ेगा। विधायक राजेश मूणत ने कहा कि नगर निगम में घोटालों और भ्रष्टाचार के कारण कांग्रेस ने महापौर एजाज ढेबर से आमजनता नाराज है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के रहते बूढ़ातालाब फव्वारा घोटाला, यूनीपोल घोटाला, स्मार्ट सिटी फंड का दुरुपयोग सहित कई घोटाले हुए।

उन्होंने कहा कि आम जनता ने कांग्रेस के कुशासन से त्रस्त होकर उसे 2023 के विधानसभा चुनाव में जड़ से उखाड़ फेंका। इसी प्रकार वह नगरी निकाय चुनावों में भी कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जनता कांग्रेस से नाराज है। लेकिन हमें चुनाव को हल्के में नहीं लेना है पूरी तैयारी के साथ, अपने-अपने क्षेत्र में प्रचार अभियान को तेज करना है। हमें अपनी तरफ से भी पूरी तैयारी करनी चाहिए। निश्चित तौर पर इसका लाभ भाजपा को मिलेगा। इस बैठक में सभी वार्डों के कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में बोले कि जो भी प्रत्याशी तय होगा बिना गुटबाजी किये ईमानदारी से कार्य करना है। विधायक राजेश मूणत ने कहा कि हमारा प्रत्याशी केवल कमल फूल है। इस बैठक में रायपुर पश्चिम विधानसभा के अभी 20 वार्डो के भाजपा जनप्रतिनिधि, मंडल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पदाधिकारी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे।

अमृत मिशन के तहत जल प्रदाय योजना के काम में आएगी तेजी

■ योजना से माना नगर पंचायत के करीब चार हजार घरों में हर घर पहुंचेगा नल से जल

रायपुर। मिशन अमृत 2.0 के अंतर्गत माना नगर पंचायत में निर्माणाधीन जल प्रदाय योजना के काम में अब तेजी आएगी। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने आज सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ फील्ड पर पहुंचकर कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने पेयजल योजना के काम में तेजी लाने तथा गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने रायपुर नगर निगम और माना नगर पंचायत के बीच पेयजल आपूर्ति में समन्वय के लिए रायपुर नगर निगम के आयुक्त को माना नगर पंचायत में पेयजल की उपलब्धता के लिए आवश्यक निर्देश दिए। विधायक मोतीलाल साहू, नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस., रायपुर के कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह और नगर निगम आयुक्त श्री अबिनाश मिश्रा भी कार्यों के निरीक्षण के दौरान मौजूद थे।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने माना नगर पंचायत में पुष्प वाटिका गार्डन में निर्माणाधीन पानी टंकी के कार्यों के निरीक्षण के दौरान पेयजल वितरण लाइन के लिए लोक निर्माण विभाग की लगभग नौ किमी की लंबाई की सड़कों को लेकर विभाग और नगर पंचायत के बीच समन्वय की कमी को भी दूर किया। उन्होंने कार्यस्थल पर ही नगरीय निकाय और लोक निर्माण विभाग के बीच जल प्रदाय परियोजनाओं में समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने और पाइपलाइन विस्तार का कार्य तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश दिए। श्री साव ने सीएसपीटीसीएल से संबंधित प्रकरणों के निराकरण के लिए ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर तत्काल परियोजना में आ रही भूमि संबंधी दिक्कतों के समाधान के निर्देश दिए।

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी मिशन अमृत 2.0 के अंतर्गत माना नगर पंचायत में पेयजल योजना तैयार की जा रही है। इसके तहत माना नगर पंचायत के करीब चार हजार घरों में नल से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। 44 करोड़ 38 लाख रुपए लागत की इस योजना का अब तक 30 प्रतिशत से अधिक काम पूरा कर लिया गया है। सितम्बर-2025 तक इसका काम पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

माना नगर पंचायत कार्यालय में निर्माणाधीन 840 किलोलीटर और पुष्प वाटिका गार्डन में निर्माणाधीन 650 किलोलीटर क्षमता की दो ओवरहेड पानी टंकियों के माध्यम से माना शहर में जलापूर्ति की जाएगी। दोनों टंकियों का काम क्रमशः 85 प्रतिशत और 75 प्रतिशत पूरा हो गया है। जलापूर्ति के लिए नगर पंचायत में करीब 66 किमी का डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन बिछाया जाएगा। इसमें से अब तक 34 किमी से अधिक पाइपलाइन बिछाया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ने सशस्त्र सेना वयोवृद्ध दिवस पर शहीद परिवारों का किया सम्मान

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले के पगुराबहार गांव में आयोजित 9वें सशस्त्र सेना वयोवृद्ध दिवस पर सेना के वीर जवानों के साहस और बलिदान को नमन किया। इस अवसर पर उन्होंने 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन कर राष्ट्रपति द्वारा सेना मेडल से सम्मानित भागलपुर निवासी 81 वर्षीय अरुण कुमार का सम्मान किया। मुख्यमंत्री ने उन्हें शाल, श्रीफल और प्रशस्ति पत्र भेंटकर उनके अदम्य साहस की सराहना की। अरुण कुमार ने अपने युद्ध के अनुभव साझा कर देशसेवा के गौरवशाली क्षणों को याद किया।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जिले के तीन शहीद सेनानियों के परिवारों को सम्मानित किया। इनमें शहीद सिपाही शिमोन केरकेट्टा, शहीद राजेश बारा और शहीद अशोक राम भगत के परिजन शामिल थे। मुख्यमंत्री ने इन परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया। शहीद हवलदार शिमोन केरकेट्टा की पत्नी तेरेसा केरकेट्टा को चलने में हो रही कठिनाई को देखते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें व्हीलचेयर प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने शहीद सिपाही शिमोन केरकेट्टा के अदम्य साहस को याद करते हुए कहा कि उन्होंने 1966 में मिजोरम में देश के दुश्मनों से लड़ते हुए प्राणों की आहुति दी। वहीं शहीद राजेश बारा ने 2002 में जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ते हुए अपने प्राण न्योछावर किए। शहीद अशोक राम भगत ने 2020 में सिक्किम के ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान देश की रक्षा करते हुए शहादत दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन वीर सपूतों के बलिदान और योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री ने भारतीय सशस्त्र सेनाओं के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के. एम. करियप्पा के योगदान को याद करते हुए कहा कि सशस्त्र सेना वयोवृद्ध दिवस हमारे जवानों और उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का दिन है। यह दिन शांति और स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्ष और बलिदान को स्मरण करता है।

डॉक्टरों ने पाइपेक पद्धति से किया पेट की झिल्ली के कैंसर का सफल उपचार

रायपुर। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में स्वास्थ्य सुविधाओं का लगातार सशक्तिकरण हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के अथक प्रयासों से राज्य की जनता को सहज और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल रहा है। वहीं नित नये वैज्ञानिक शोध, परीक्षण और निष्कर्ष पर आधारित आधुनिक चिकित्सा प्रणाली की मदद से आज मनुष्य कई गंभीर बीमारी से ठीक होकर निकल रहे हैं।

डॉक्टरों की उपचार प्रक्रिया और मरीज की सकारात्मक सोच की बदौलत कैंसर जैसे असाध्य रोग भी अब साध्य हो चले हैं। इसी क्रम में हाल ही में पं. जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय स्थित क्षेत्रीय कैंसर संस्थान के आंकोसर्जरी (कैंसर सर्जरी) विभाग के डॉक्टरों की टीम ने पेट की झिल्ली के (पेरिटोनियम) कैंसर से पीड़ित महिला का उपचार पाइपेक पद्धति से कर महिला के बहुमूल्य जीवन को बचाने में अपनी अहम

भूमिका निभाई है।

संभवत: मध्य भारत के किसी भी शासकीय कैंसर अस्पताल में इस पद्धति से पहली बार इलाज कर डॉक्टरों ने मरीज के पेट की झिल्ली के कैंसर का इलाज किया है। पाइपेक यानी प्रेशराइज्ड इंट्रापेरिटोनियल एरोसोलाइज्ड कीमोथेरेपी, कैंसर बीमारी में दी जाने वाली कीमोथेरेपी का ही एक प्रकार है। यह उदर गुहा में दबाव के साथ कीमोथेरेपी को पहुंचाती है जिससे कैंसर कोशिकाओं को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। कैंसर सर्जन डॉ.(प्रो.) आशुतोष गुप्ता के नेतृत्व में लेप्रोस्कोपिक विधि से न्यूनतम इनवेसिव प्रक्रिया के अंतर्गत किये गये इस उपचार विधि में कीमोथेरेपी को एक मशीन के जरिये एरोसोल के रूप में दिया जाता है जिससे कैंसर उत्तकों में दवा का प्रभाव ज्यादा होता है और कैंसर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। ओड़िशा की रहने वाली 54 वर्षीय महिला मरीज को उपचार के पांच दिन बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। उपचार के बाद वह अब ठीक है और फॉलोअप के लिए आ रही है।

पाइपेक एक लेप्रोस्कोपिक प्रक्रिया है। इसका मतलब है कि डॉक्टर मरीज के पेट में एक या दो छोटे छेद करके इस प्रक्रिया को पूरी करते हैं जिन्हें एक्सेस पोर्ट भी कहा जाता है।

क्षेत्रीय कैंसर संस्थान के संचालक एवं पं. नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. विवेक चौधरी ने पहली बार इस नये विधि से किये गये सफल उपचार के लिए कैंसर सर्जरी विभाग की पूरी टीम को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि यह एक सुरक्षित और प्रभावी उपचार प्रक्रिया है जो कीमोथेरेपी के प्रभाव को बढ़ाता है। कोलोरेक्टल कैंसर, डिम्बग्रंथि का कैंसर और गैस्ट्रिक कैंसर जैसे कैंसर बीमारियों में कीमोथेरेपी के नये विकल्प के रूप में इसे अपनाया जा सकता है। प्रयास करेंगे कि भविष्य में कैंसर के अन्य मरीजों को भी इस उपचार सुविधा का लाभ मिल सके।

अम्बेडकर अस्पताल अधीक्षक डॉ. संतोष सोनकर ने कहा कि अम्बेडकर अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उपचार हेतु किये जा रहे निष्ठापूर्ण प्रयासों ने लोगों का विश्वास इस संस्था के प्रति सदा से ही बनाये रखा है।

कैंसर सर्जन डॉ. आशुतोष गुप्ता के अनुसार, प्रेशराइज्ड इंट्रापेरिटोनियल एरोसोलाइज़्ड कीमोथेरेपी एक तकनीक है जो दबाव के तहत एरोसोल के रूप में उदर गुहा में कीमोथेरेपी को पहुंचाती है। एरोसोल दो शब्दों से मिलकर बना है। एयरो यानी विशेष हवा और सोल अर्थात् द्रव में अत्यंत छोटे कणों के रूप में पदार्थ का मिश्रण। दबावयुक्त एरोसोल पूरे पेट में कीमोथेरेपी को समान रूप से वितरित करता है।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला-दुर्ग (छ.ग.)

परिशिष्ट- दो (नियम 4.4.2)

निविदा प्रकाशन बाबत्

निविदा विज्ञप्ति क्रमांक 343 दुर्ग, दिनांक 11/01/2025

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दुर्ग (छ.ग.) की ओर से कार्यालयीन कार्य हेतु वर्किंग लंच / नाश्ता/मीटिंग हॉल/किराये का कमरा/ होर्डिंग, वॉल राईटिंग, माईकिंग / प्रपत्र प्रचार-प्रसार सामग्री के मुद्रण एवं फोटोस्टेट एवं किराये के वाहन हेतु वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के लिए मुहरबंद लिफाफा में खुली निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रपत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रति निविदा फार्म रू. 1000/- (अक्षरी-रू. एक हजार मात्र) का नगद भुगतान कर निविदा प्रकाशन के दिनांक से 31/01/2025 तक सायं 5.00 बजे तक कार्यालयीन दिवस में प्राप्त किये जा सकते हैं।

निविदा बिक्री की अंतिम तिथि- 04/02/2025 को शाम 5.00 बजे तक
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि - 05/02/2025 को दोपहर 3.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि - 05/02/2025 को दोपहर 4.00 बजे तक

स्थान :- कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दुर्ग (छ.ग.)

जी-242505318/4

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला-दुर्ग (छ.ग.)

नई दिल्ली विधानसभा सीट पर फंस गए हैं केजरीवाल

संतोष पाठक

आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भले ही एक बार फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हो लेकिन इस बार वह बुरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के मजबूती से दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारियों ने तो आम आदमी पार्टी सरकार की वापसी पर प्रश्नचिन्ह लगा ही दिया है लेकिन इस त्रिकोणीय लड़ाई में केजरीवाल की अपनी सीट भी फंसती हुई नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल इस बात को काफी पहले ही समझ गए थे, इसलिए वह लगातार इंडिया गठबंधन की एकता की बात उठाने लग गए थे। यहां तक कि केजरीवाल ने डीएमके सुप्रीमो एवं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, शरद पवार, अखिलेश यादव और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित कई नेताओं से राहुल गांधी को समझाने की गुहार भी लगाई। लेकिन अरविंद केजरीवाल की असलियत से वाकिफ राहुल गांधी ने यह साफ कर दिया कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में अपने आप को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ेगी। सीलमपुर की अपनी पहली चुनावी रैली में राहुल गांधी ने जिस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ-साथ आप मुखिया अरविंद केजरीवाल, पर भी जमकर निशाना साधा,उससे यह साफ हो गया कि राहुल गांधी अपनी पार्टी को समाप्त कर केजरीवाल की मदद कतई नहीं करेंगे। कांग्रेस के इस स्टैंड ने अरविंद केजरीवाल की विधायकी पर भी तलवार लटका दिया है। केजरीवाल को अब यह डर सताने लगा है कि अब वह अपनी विधानसभा सीट नई दिल्ली से भी चुनाव हार सकते हैं। केजरीवाल के इस डर के पीछे ठोस कारण है। अरविंद केजरीवाल वर्ष 2013 के अपने पहले विधानसभा चुनाव में दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव हराकर, पहले विधायक बने थे और फिर कांग्रेस के ही 8 विधायकों के समर्थन से पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। बताया तो यहां तक जाता है कि 2013 में शीला दीक्षित को चुनाव हराने के लिए कांग्रेस के कई नेताओं ने भी अरविंद केजरीवाल की मदद की थी। लेकिन दिल्ली में पार्टी को फिर से मजबूत बनाने के मिशन में जुटे राहुल गांधी ने इस बार नई दिल्ली विधानसभा सीट से केजरीवाल के खिलाफ स्वर्गीय शीला दीक्षित के बेटे और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित को उतार कर लड़ाई को त्रिकोणीय और दिलचस्प बना दिया है। अगर आप 2020 के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को मिले वोटों की तुलना 2015 के विधानसभा चुनाव से करेंगे तो आपको यह समझ आ जाएगा कि केजरीवाल को अपनी ही विधानसभा सीट पर डर क्यों लग रहा है ? वर्ष 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में आप मुखिया अरविंद केजरीवाल को 57,213 वोट मिले थे। लेकिन वर्ष 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में दिल्ली के मुख्यमंत्री होने और कुल मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी होने के बावजूद केजरीवाल को मिले वोटों में भयानक गिरावट आ गई थी। 2015 के चुनाव में जिन केजरीवाल को 57,213 वोट मिले थे, उन्ही केजरीवाल को 2020 के चुनाव में 46,758 वोट ही मिल पाए थे। पिछली बार यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की जीत का अंतर 21,697 था लेकिन उस चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार को सिर्फ 3,220 मत ही मिल पाए थे। इस बार शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं और अगर वह आखिर तक पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ पाते हैं तो फिर केजरीवाल के लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएगी। क्योंकि इस बार दिल्ली के एक और पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे प्रवेश वर्मा भी नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा उम्मीदवार के तौर पर प्रवेश वर्मा और कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर संदीप दीक्षित के मजबूती से चुनाव लड़ने की वजह से वोटों का बिखराव होगा,जिसका सीधा-सीधा नुकसान अरविंद केजरीवाल को ही होगा। इसलिए आम आदमी पार्टी के तमाम नेता और स्वयं अरविंद केजरीवाल भी अंदर से डरे हुए हैं।

दिल्ली चुनाव में कांग्रेस को हल्के में मत लेना

अभिनय आकाश

पहले नरेंद्र मोदी 400 पार की बात कर रहे थे। छाती फैलाकर चार सौ पार। लेकिन चुनाव के बाद उन्होंने संविधान को ऐसे सिर पर लगाया। ये काम कांग्रेस पार्टी ने करवाया है। कांग्रेस पार्टी ने साफ उनको कह दिया कि देखो बाकी सब ठीक है। लेकिन संविधान पर आक्रमण किया तो हिंदुस्तान आपको माफ नहीं करेगा, देश आपको माफ नहीं करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नारायणा गांव में लोहड़ी के कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे। ठीक उसी वक्त वहां से 23 किलोमीटर दूर सीलमपुर में एक चुनावी रैली में नजर आए राहुल ने अपने 21 मिनट के संबोधन में जिस अंदाज में पीएम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर निशाना साधा, उसी तेवर में आम आदमी पार्टी (आप) और केजरीवाल पर भी आक्रमक नजर आए। राहुल ने कहा कि केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा प्रचार किया कि दिल्ली को साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा। पेरिस बना दूंगा। अब देखिए हुआ क्या केजरीवाल जी ने अडानी जी के बारे में कुछ बोला है। जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूं न मोदी जी और न केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द निकलता है। केजरीवाल जी देश के सामने कहे कि वो आरक्षण बढ़ाना चाहते हैं और जाति जनगणना करना चाहते हैं।

दिल्ली के सीलमपुर से राहुल गांधी ने कांग्रेस के कैंपेन का आगाज कर दिया है। राहुल ने अपने चुनावी प्रचार की शुरुआत के लिए मुस्लिम बहुल क्षेत्र को चुना है। 5 फरवरी में दिल्ली में वोटिंग से तीन हफ्ते पहले राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रचार की शुरुआत कर दी। हालांकि उन्होंने जिस विधानसभा सीट से प्रचार अभियान शुरू किया है वो एक रणनीति के तहत किया गया है। सीलमपुर मुस्लिम बहुल इलाका है और यहां मुस्लिम वोटरों की संख्या 55 से 60 प्रतिशत तक है। सीलमपुर हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है। लेकिन 2015 से इस सीट पर कांग्रेस लगातार हार रही है। जय भीम, जय संविधान के नारे के साथ राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार का आगाज किया है। यानी सीधे तौर पर राहुल गांधी एक साथ दलित और मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश में जुट गए हैं। आम आदमी पार्टी से पहले मुस्लिम

दिल्ली के सीलमपुर से राहुल गांधी ने कांग्रेस के कैंपेन का आगाज कर दिया है। राहुल ने अपने चुनावी प्रचार की शुरुआत के लिए मुस्लिम बहुल क्षेत्र को चुना है। 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग से तीन हफ्ते पहले राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रचार की शुरुआत कर दी।

कांग्रेस के कोर वोटर्स थे। कांग्रेस की नजर इसी वोट बैंक पर है। सीलमपुर के आसपास के सीटों पर भी यही समीकरण लागू होता है।

सीलमपुर से चुनाव प्रचार का आगाज करके कांग्रेस ने साफ किया कि इस बार दिल्ली का चुनाव एक रणनीति के तहत है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी जहां एक तरफ हिंदुत्व की पिच पर है। राहुल गांधी मुस्लिम वोटरों को साधने में हैं और नजर सीधा दलित वोटर्स पर भी है। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस के अब तक के आक्रमक अंदाज और तेवरों को पार्टी नेतृत्व ने अपने चुनाव अभियान में अगले पायदान पर ले जाने का जज्बा दिखाया तो माना जा रहा है कि राजधानी का ये चुनाव बेहद रोचक मोड़ ले सकता है। दिल्ली के एमसीडी इलेक्शन में मुस्लिम बहुल इलाके में कांग्रेस दोबारा से मुस्लिमों का विश्वास जीतने में कामयाब रही थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में आप के साथ गठबंधन के बाद स्थिति बदल गई। यही वजह है कि अब कांग्रेस मुस्लिम वोटों को फिर से जोड़ने की कवायद में है।

जिस शराब नीति घोटाले ने आप को बड़े संकट में डाला, उसकी शिकायत कांग्रेस ने ही की थी। हाल ही में महिला सम्मान योजना में फर्जीवाड़े की आशंका की शिकायत लेकर भी कांग्रेस के संदीप दीक्षित ही उपराज्यपाल के पास पहुंचे। उन्होंने यह भी कहा है कि पंजाब पुलिस उम्मीदवारों की जासूसी कर रही है और दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पंजाब से कैश लाया जा रहा है। कांग्रेस को उम्मीद है कि उसके कोर वोटर फिर से वापस आ जाएंगे क्योंकि आम आदमी पार्टी इस बार बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे पर है। ओवैसी भी मुस्लिम बहुल इलाकों में उम्मीदवार उतार रहे हैं। मुस्लिम वोटों का बंटना तय है। ऐसे में आम आदमी पार्टी मुस्लिम वोटों पर चुप रहकर जाट आरक्षण को बड़ा मुद्दा बनाने में जुट गई है। कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि वो अपने पुराने मतदाता वर्ग को वापस अपनी तरफ़ आकर्षित करे। राजनीति के जानकार मानते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो इसकी सीधी क़ीमत आम आदमी पार्टी को चुकानी पड़ सकती है। दिल्ली में कांग्रेस की राजनीतिक विरासत रही है। वहीं मुसलमान मतदाता असमंजस में नज़र आ रहे हैं। यदि कांग्रेस की तरफ़ गए तो कई सीटों के नतीजे बदल सकते हैं।

1998 से 2013 तक लगातार तीन विधानसभा चुनाव जीतने वाली कांग्रेस 2015 के चुनाव में खाता तक नहीं खोल पाई। पार्टी को सिर्फ 9.65% वोट मिले। वहीं, 2013 के चुनाव में कांग्रेस ने 24.55% वोट के साथ 8 सीटें जीती थीं। दिल्ली में पार्टी की दुर्गति यहीं नहीं रुकी। 2020 में वोट गिरकर 4.26% रह गया। ऐसे में दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 25-26 ऐसी हैं, जहां मुस्लिम, निम्न मध्यमवर्गीय और अनुसूचित जाति एवं जनजाति मतदाता बहुलता में है। लोकसभा चुनाव में भी इन सीटों पर पार्टी को अच्छा वोट मिला है। इन सीटों में मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, बाबरपुर, सीमापुरी, सीलमपुर, मुस्तफाबाद, गोकलपुर, चांदनी चौक, मटिया महल और बल्लीमारान प्रमुख है। दिल्ली में पांच ऐसी सीटें हैं, जो मुस्लिम बाहुल्य है। इनमें ओखला (43 प्रतिशत), सीलमपुर (50 प्रतिशत), मुस्तफाबाद (37 प्रतिशत), बल्लीमारान (38 प्रतिशत), मटियामहल (49 प्रतिशत) आदि शामिल हैं। कांग्रेस इनमें तो मुस्लिम प्रत्याशी उतार ही रही है, कई हिंदू बाहुल्य सीटों पर भी मुस्लिम प्रत्याशी उतारने की तैयारी है। मकसद सिर्फ यही है कि किसी तरह से वोट प्रतिशत बढ़ जाए।

कांग्रेस की कोशिश अपना वोट बैंक वापस हासिल करने की है, जिस पर कब्जा कर आप दिल्ली की राजनीति में अजेय बन गई है तो पिछले तीनों लोकसभा चुनाव में सभी सातों सीटें जीतने के बावजूद हर विधानसभा चुनाव में अपमानजनक हार का कड़वा घूंट पीने को मजबूर बीजेपी लगभग 27 साल से दिल्ली की सत्ता से वनवास झेल रही है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर तक कमल खिल जाने के मद्देनजर तो यह चिराग तले अंधेरा जैसी स्थिति है, पर इस बार भी उजाला हाथ की करामात पर ज्यादा निर्भर करेगा। कांग्रेस अपने वोट बैंक का एक ठीकठाक हिस्सा केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा देगा। कुल मिलाकर कहें तो भले ही कांग्रेस दिल्ली में बहुत कुछ ना कर पाए, लेकिन कांग्रेस जहां खड़ी है यहां से जितना भी आगे बढ़ेगी उससे नुक़सान आप को ही होगा। कांग्रेस वोट प्रतिशत में जितना भी आगे बढ़ेगी, वह आम आदमी पार्टी की ही कटौती करेगी।

पुराण दिग्दर्शन .... तीसरा अध्याय

वेदों में अष्टादश पुराणों के नाम

(गतांक से आगे...)

आज भले ही ग्रन्थकार लोग किसी एक ही विषय के विशेषज्ञ होते हों और अपने परिमित शब्दों में एकमात्र उसी रजिस्टर्ड विषय पर लिखने की योग्यता रखते हों, तथा नवीन विषय के प्रतिपादन में चौकड़ी भूल जाते हों, परन्तु वेदव्यास जी जैसे सर्वतोमुख ज्ञान की पराकाष्ठा तक पहुँचे हुये त्रिकलश महर्षि के विषय में जिनका कि अवतार ही वेदादि ग्रन्थों के संकलनार्थ हुवा हो, ऐसी विभिन्न भाषाओं को न लिख सकने की सम्भावना करना भी महामूर्खता है।

जो लोग महाभारत को सर्वांश में प्रसाद गुणयुक्त समझते हैं, बास्तव में उन्होंने समस्त महाभारत को पढ़ा ही नहीं। क्योंकि सब पण्डित जानते हैं और स्वयं वेदव्यास जी ने भी अनुक्रमणिकाध्याय में। कर दिया है, कि महाभारत में आठ हजार आठ सौ कूट जिनका समझना हमारे लिए अत्यन्त कठिन है। महाभारत में लिखा है कि- अष्टौ श्लोकसहस्राणि अष्टौ श्लोकशतानि च । अहं वेद्मि शुको वेत्ति, संजयो वेत्ति वा न बा।। (महाभारत आदिपर्व 18 । 1)

अर्थात्- (व्यास जी कहते हैं) महाभारत के आठ हजार आउ सौ श्लोकों को मैं जानता हूं- और शुकदेव जानता है, परन्तु संजय जानता है या नहीं जानता, सो ठीक नहीं कहा जा सकता। जिस पुरुष को इन कूटश्लोकों के साथ अपनी बुद्धिमत्ता की तुलना कर देखनी हो, उसे महाभारत के विदुर-प्रजागर का पाठ करना चाहिए।

गोकर्णासुमुखी कृतेन इषुणा खचरस्य सुत: खचर: आदि श्लोकों का भी अर्थ लगाना चाहिए। सच तो यह है कि यदि महाभारत पर नीलकण्ठी व्याख्या न होती तो इसका बहुत सा अंश हमारे लिये अज्ञात रहता। इसलिये महाभारत को सरल समझ बैठना निरी भूल है।

क्रमश: ...

राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस

शौर्य पुंज

देश में आज नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को सेलिब्रेट करने के लक्ष्य से इसकी शुरुआत की थी। भारत में स्टार्टअप की उपलब्धियों की सराहना करने के लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। भारत के युवाओं के लिए नवाचार और अर्थव्यवस्था में उनके योगदान पर चर्चा करने के लिए स्टार्टअप उद्यमियों को एक मंच प्रदान करने के लिए भी यह दिन मनाया जाता है।

15 जनवरी 2022 को, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस को अपनाने की घोषणा की। उसी वर्ष भारत ने पहला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया। नवोदित उद्यमियों

के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत के दौरान, पीएम मोदी ने पिछले कुछ वर्षों में स्टार्टअप्स के विकास की प्रशंसा की।

स्टार्टअप कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसने अभी कामकाज शुरू किया है। आप अकेले या कुछ लोगों के साथ मिलकर कंपनी की नींव रखते हैं जिसे इनक्युबेशन कहते हैं। यहां पर लोग अपनी-अपनी कुशलता और विशेषज्ञता लेकर आते हैं और नए कारोबारी आइडिया पर मिलकर काम करते हैं। इस तरह की कंपनी के जरिए ग्राहकों को एक यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस दी की जाती है।

देश में तेजी से बढ़ता स्टार्टअप कल्चर

कॉमर्स मिनिस्ट्री के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत में साल 2016 के स्टार्टअप्स की संख्या 471 रही, जोकि 2022 में बढ़कर 72,993 हो गई। यानी स्टार्टअप की संख्या में रिकॉर्ड 15,400% की ग्रोथ दर्ज की गई है। भारत ने हाल के वर्षों में स्टार्टअप्स के क्षेत्र में एक क्रांति देखी है, और यह दिवस उन महत्वाकांक्षी विचारों का जश्न है, जो न केवल हमारी अर्थव्यवस्था को बदल रहे हैं, बल्कि समाज की बड़ी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। 'स्टार्टअप इंडिया' पहल ने न केवल भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को सशक्त बनाया, बल्कि युवाओं को अपने सपनों को हकीकत में बदलने का हौसला भी दिया। यह दिन भारतीय युवाओं को प्रेरित करने का कार्य करता है ताकि वे नवाचार, उद्यमिता और आर्थिक वृद्धि में सक्रिय रूप से भाग लें। मेक-इन-इंडिया जैसे अभियानों को बढ़ावा देने के लिए भी इस दिन विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर विभिन्न सम्मेलन, कार्यशालाएं और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इस दिन, स्टार्टअप्स के लिए विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए मंच उपलब्ध कराए जाते हैं। सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं ताकि उत्कृष्टता को सम्मानित किया जा सके। इस दौरान इनोवेशन वीक का आयोजन भी किया जाता है, जो युवाओं में उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहित करता है।

भीषण आग से अमेरिका ही नहीं, दुनिया सबक ले

ललित गर्ग

अमेरिका के लॉस एंजेलिस में जंगल की बेकाबू आग फैलने, भारी तबाही, महाविनाश और भारी जन-धन की क्षति ने साबित किया है कि दुनिया की नंबर एक महाशक्ति भी कुदरत के रौद्र के सामने बौनी ही साबित हुई है। न केवल अमेरिका के इतिहास में बल्कि दुनिया के इतिहास यह जंगल की आग सबसे भयावह, सर्वाधिक विनाशकारी एवं डरावनी साबित हुई है। आग धीमी होने का नाम नहीं ले रही है। बल्कि और तेजी से बढ़ती जा रही है और इसका कारण 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं हैं। ये हवाएं इस आग को और भड़का रही हैं, तबाही का मंजर बन रही है, जिसे रोकना अमेरिका प्रशासन के लिए एक चुनौती बन गया है। अमेरिकी सेना के सी-130 विमान और फायर हेलीकॉप्टर हर संभव कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हवा की गति और आग की लपटों की ताकत के आगे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के तमाम प्रयास नाकाफी एवं बेबस साबित हो रहे हैं।

अनियंत्रित विकास, पर्यावरण की घोर उपेक्षा एवं भौतिकतावादी सोच इस आग का बड़ा कारण है। खरबों रुपये की संपत्ति और प्राकृतिक संपदा के नष्ट होने के अलावा करीब दो लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। आलीशान बंगलों, सरकारी संरचना तथा नागरिक सुविधा के साधनों के स्वाह होने के साथ करीब 24 लोगों के मारे जाने की खबर है। करीब दो लाख लोगों को घर-बार छोड़कर जाने के लिये तैयार रहने को कहा गया है। अमेरिका संस्कृतिविहीन देश बनता जा रहा है- यह राष्ट्र भौतिक विकास, पर्यावरण उपेक्षा एवं शस्त्र संस्कृति पर सवार है। वहां के नागरिक अपने पास जितने चाहें, उतने भौतिक संसाधन रख सकते हैं। सुविधावादी जीवनशैली के शिखर एवं तमाम सुरक्षा परिस्थितियों में जीने के बावजूद यह देश आज कितना असहाय एवं बेबस है। विकास की बोली बोलने वाला, विकास की जमीन में खाद एवं पानी देने वाला, दुनिया में आधुनिकता, तकनीक एवं विकास की

आंधी लाने वाला अमेरिका जब खुद ऐसी भीषण आग की तबाही का शिकार होने लगा तो उसकी नींद टूटी हैं, उसे अपनी असलियत का पता लगा।

दुनिया को सुरक्षा एवं विकास का आश्वासन देने वाला देश आज खुद अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है। वहां के आधुनिक तकनीक से लेस दमकल विभाग व सुरक्षा बलों की तमाम कोशिशों के बावजूद आग बेकाबू है। लोग असहाय होकर अपनी जीवन भर की पूंजी को स्वाह होते देख रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के चलते तल्ख होते मौसम से हालात और खराब होने की आशंका जतायी जा रही है। आग के बाद का जो मंजर नजर आ रहा है उसे देखकर ऐसा लगता है मानो कोई बम गिराया गया हो। विडंबना यह है कि आपदा में अवसर तलाशने वाले कुछ लोग खाली कराये गए घरों में लूटपाट से भी बाज नहीं आ रहे हैं। हॉलीवुड हिल्स इलाके में करीब साढ़े पांच हजार से अधिक इमारतों के नष्ट होने की खबर है। कई नामी फिल्मी हस्तियों के घर, जैसे बिली क्रिस्टल, मैंडी मूर, जेमी ली कर्टिस और पेरिस हिल्टन शामिल हैं एवं व्यावसायिक इमारतें व सार्वजनिक संस्थान आग की भेंट चढ़े हैं। वहां की आस्थाएं एवं निष्ठाएं इतनी जख्मी हो गयी कि विश्वास जैसा सुरक्षा-कवच मनुष्य-मनुष्य के बीच रहा ही नहीं। साफ चेहरों के भीतर कौन कितना बदसूरत एवं उन्मादी मन समेटे है, कहना कठिन है। अमेरिका की विकास की होड़ एवं तकनीकीकरण की दौड़ पूरी मानव जाति को ऐसे कोने में धकेल रही है, जहां से लौटना मुश्किल हो गया है। ईश्वर की बनायी संरचना में दखल का ही परिणाम है कि प्रकृति इतना रौद्र एवं विध्वंसक रूप धारण किया है।

अमेरिका आज दुनिया में प्रकृति के दोहन, अपराध का सबसे बड़ा अड्डा है और हिंसा की जो संस्कृति उसने दुनिया में फैलाई, आज वह स्वयं उसका शिकार है। अमेरिका के इतिहास में यह जंगल की आग सबसे भयावह साबित हुई है। चिंता की बात यह है कि इलाके में हाल-फिलहाल बारिश होने की संभावना नहीं है, जिससे जंगल की आग जल्दी काबू में आ सकती। एक बड़े इलाके में बिजली आपूर्ति ठप होने व पानी की आपूर्ति में बाधा संकट को और बढ़ा रही है। लोगों की सुरक्षित स्थानों में जाने के लिये अफरा-तफरी से जगह-जगह ट्रैफिक जाम लग रहे हैं। पानी का दबाव कम होने से दमकल कर्मियों को आग बुझाने में परेशानी आ रही है। घोर अव्यवस्था एवं कुप्रशासन फैला है। दरअसल यह आग लॉस एंजेलिस के उत्तरी भाग में लगी, जिसने बाद में कई बड़े शहरों को अपनी चपेट में ले लिया। तेज हवाओं व सूखे मौसम के कारण आग ज्यादा भड़की है। सूखे पेड़-पौधे तेजी से आग की चपेट में आ गए। हालांकि, आग लगने का ठोस कारण अभी तक पता नहीं चला है। हकीकत है कि जंगलों में 95 फीसदी आग इंसानों द्वारा ही लगायी जाती है। वैसे जलवायु परिवर्तन प्रभावों के चलते बदले हालात में अब पूरे साल आग लगने की आशंका बनी रहती है।

अमेरिका दुनिया पर अपना एकछत्र शासन चाहता है। कनाडा, ग्रीनलैंड एवं पनामा को अमेरिका में शामिल करना चाहते हैं। मतलब सीधा सा है जिसकी लाठी उसकी भैंस यानी पावर और पैसे के बल पर खुद को बलवान और सुपरपावर मुल्क समझने वाला अमेरिका एक आग के आगे बेबस नजर आ रहा है। कैलिफोर्निया के दक्षिणी हिस्से में शुरू हुई इस जंगल की आग ने अब लॉस एंजेलिस जैसे बड़े शहर को राख बना दिया है। पैलिसेड्स में 20 हजार एकड़, ईटन में 14 हजार एकड़, कैनेथ में 1000 एकड़, हर्स्ट में 900 एकड़, लिडिआ में 500 एकड़ में आग फैली है। इन इलाके में राख के बारीक कणों व धुएं की चादर के कारण स्थानीय स्वास्थ्य इमरजेंसी घोषित की गई है। लोगों का जीवन इन सभी स्थानों पर दुर्भर हो गया है। लॉस एंजलिस की इस आग ने न केवल जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि सूखे और जलवायु परिवर्तन के प्रति गंभीर चेतावनी भी दी है।

आज अमेरिका विकास की चरम अवस्था पार कर चुका है। यह आशंका सदैव बनी रही है कि अनियंत्रित विकास एवं प्रकृति विनाश के प्रति समय रहते नहीं चेतने की कीमत सृष्टि के विनाश एवं मानवता के धंस से चुकानी होती है, धरती का पर्यावरण नष्ट हो जाता है। धरती पर मंडराते इसी संकट का प्रतीक है यह आग। बात बहुत ही सीधी सी है कि जब तक प्रकृति डराती नहीं विकास की राहें ऐसे ही बेतहाशा एवं अनियंत्रित आगे बढ़ती रहती हैं। किंतु जब प्रकृति मुस्कुराना भूल जाए तो वह विकास, विकास नहीं रहता। वहाँ कृत्रिमता दस्तक देने लगती है, धरती करवट बदलने लगती है, अम्बर चीत्कार कर उठता है तब मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि अब विनाश की पदचाप सुनाई देने लगी हैं। ज़िद एवं अहंकार में बाज़ी पलट सकती है, वरना विनाश का दावानल अमेरिका की आग की तरह सब कुछ राख कर देता है। 'मन जो चाहे वही करो' की मानसिकता वहां पनपती है जहां ईश्वर की सत्ता एवं इंसानी रिश्तों के मूल्य समाप्त हो चुके होते हैं, ऐसी स्थिति में शक्तिशाली देश अपनी अनंत शक्तियों को भी बौना बना देता है। यह दकियानूसी ढंग है भीतर की अस्तव्यस्तता को प्रकट करने का। ऐसे देशों एवं लोगों के पास सही जीने का शिष्ट एवं अहिंसक सलीका नहीं होता। वक्त की पहचान नहीं होती। ऐसे लोगों में संतुलित विकास, शांतिपूर्ण सहजीवन, सृष्टि का संतुलन एवं सर्वोच्च ईश्वर सत्ता के प्रति सम्मान आदि का कोई खास ख्याल नहीं रहता। पक्षी भी एक विशेष मौसम में अपने घोंसले बदल लेते हैं। पर मनुष्य अपनी वृत्तियां नहीं बदलता। वह अपनी वृत्तियां तब बदलने को मजबूर होता है जब दुर्घटना, दुर्दिन या दुर्भाग्य का सामना होता है। अमेरिका की आग पक्षियों के इस संदेश को समझने व समय रहते जागने को कह रही है। इस आग से अमेरिका ही नहीं, समूची दुनिया को सबक लेने की जरूरत है।

आज का इतिहास

1943 इंडोनेशिया के अंबोन द्वीप पर अमेरिकी वायुसेना का पहला हवाई हमला हुआ।
1943 इराक ने द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया, जर्मनी, इटली और जापान ने युद्ध घोषित किया।
1947 विंसेंट ऑरियल फ्रांस के राष्ट्रपति चुने गये।
1964 संगीत हैलो, डॉली! ब्रॉडवे पर सेंट जेम्स थिएटर में खोला गया, और दस टोनी अवार्ड जीतने के लिए आगे बढ़ता गया, उसने एक रिकॉर्ड स्थापित किया जो 35 वर्षों तक कायम रहा था।
1969 सोवियत अंतरिक्ष यानों के बीच पहली बार अंतरिक्ष में सदस्यों को आदान प्रदान हुआ।
1969 चेकोस्लोवाकिया थियोरपियर वर्ष के सोवियत आक्रमण के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन के रूप में स्टूडेंट जान पालक ने वेन्सलाग स्क्वायर में खुद को आग लगा ली।
1986 इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, एक मानक संगठन है जो इंटरनेट मानकों को विकसित और बढ़ावा देता है, इसकी पहली बैठक हुई, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका-सरकार द्वारा वित्त पोषित शोधकर्ता शामिल हैं।
1991 अमेरिका और उसके 27 सहयोगी देशों ने कुवैत पर कब्जे के लिए हमला किया है।
1992 2 शेक्सपियरियन एक्टर्स न्यूयॉर्क शहर के कॉर्ट थियेटर में खुलता है। इसने 29 प्रदर्शन किए।
2002 संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद ने अलक़ायदा पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया।
2005 जॉर्ज डब्ल्यू बुश दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने।
2006 समाजवादी नेता माइकल बैशलेट चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति चुनी गयीं।
2008 स्पैनिश राष्ट्रगान, शब्द मार्चा रियल के लिए गीत के प्रस्ताव के पांच दिन बाद, स्पेनिश ओलंपिक समिति ने व्यापक आलोचना के कारण प्रस्ताव वापस ले लिया।
2011 लीबिया के मुअम्मर अल-गद्दाफी दुनिया के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले नेता होने से 24 महीने से कम समय में हैं। वह पहले ही 41 साल तक सत्ता में बने रहे हैं।
2011 न्यू यॉर्क जेट्स ने न्यू इंग्लैंड पैट्रियट्स को हराया। यह एनएफएल इतिहास का सबसे बड़ा अपसेट है।
2012 अमेरिकी कांग्रेस ने अंग्रेजी विकिपीडिया वेबसाइट को बंद करने के लिए एंटी-पायरेसी कानून प्रस्तावित किया है। अंग्रेजी विकिपीडिया और इसके खिलाफ विरोध किया है।
2013 कनाडा के सिर्के डु सॉलील ने मजबूत लूनी और बढ़ती लागत के कारण 400 नौकरियों में कटौती की।

चुनावी जीत की नई इबारत लिखती महिला मतदाता

ललित गर्ग

नये अध्ययन से यह भी खुलासा हुआ है कि महिला साक्षरता में वृद्धि हुई है जिसका सीधा असर महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ने से है। महिला साक्षरता में एक फीसदी की वृद्धि से महिला मतदाताओं की संख्या में पच्चीस फीसदी तक का इजाफा हो सकता है।

चुनावों में विभिन्न राजनीतिक दल महिलाओं को लुभाने के लिये आकर्षक कल्याणकारी योजनाओं एवं मुफ्त की सुविधाएं देने की बढ़-चढ़ कर घोषणाएं करने लगे हैं। महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाई गईं कल्याणकारी योजनाएं एवं मुफ्त की सुविधाएं अब गेमचेंजर बन रही हैं। महिलाओं के खाते में सीधे नगद ट्रांसफर की जाने वाली स्कीम तो भारत की राजनीति में वोट बटोरने का एक जांचा-परखा एवं सशक्त माध्यम बन गया है। यूं तो लम्बे समय से महिलाओं को लेकर तरह-तरह की घोषणाएं होती रही है लेकिन मध्य प्रदेश में इस योजना की कामयाबी के बाद यही कहानी महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखण्ड में दोहरायी गयी है। जिससे चुनावों में लगातार महिला मतदाताओं का उत्साह बढ़ता जा रहा है और किसी की दल की जीत हार में उसकी भूमिका भी स्पष्ट होती जा रही है। इसी विषय को लेकर एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि महिला केंद्रित योजनाओं के कारण इन महिला मतदाताओं की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 2014 में कुल मतदाता 83.4 करोड़ थे, जो 2024 में बढ़कर 97.8 करोड़ हो गये हैं। इसमें महिला मतदाता की संख्या सबसे ज्यादा बढ़ी है। एसबीआई रिसर्च टीम की रिपोर्ट के मुताबिक देश में अब 100 पुरुष मतदाताओं पर 95 महिला मतदाता की संख्या है। पिछले दस वर्षों में जिन नौ करोड़ नये वोटरों ने वोट दिया, उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी 5.3 करोड़ है। महिलाओं का मतदान के प्रति बढ़ता रूझान लोकतंत्र की मजबूती के लिये एक शुभ संकेत है।

नये अध्ययन से यह भी खुलासा हुआ है कि महिला साक्षरता में वृद्धि हुई है जिसका सीधा असर महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ने से है। महिला साक्षरता में एक फीसदी की वृद्धि से महिला मतदाताओं की संख्या में पच्चीस फीसदी तक का इजाफा हो सकता है। दिलचस्प पहलू यह भी कि एससी और एसटी वर्ग में मतदान में लगातार इजाफा हुआ, वहीं सामान्य वर्ग में कम हुआ। अब सरकारें बनाने में महिला मतदाताओं की भूमिका लगातार बढ़ती एवं निर्णायक होती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीन बार के शासनकाल में विकास पर जोर देने के साथ-साथ महिला उत्थान पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया। महिलाओं को हर क्षेत्र में प्रोत्साहन मिल रहा है, स्वतंत्र पहचान मिल रही है और वे राजनीति के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा, क्षमता एवं कौशल का लोहा मनवा रही है। मोदी सरकार ने 27 साल से भी ज्यादा इंतजार के बाद पहली बार महिला आरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित कराया। इस बीच मोदी सरकार ने महिलाओं को लेकर बनाई गई योजनाओं का नाम भी ऐसे रखा, जो सीधे महिलाओं के दिल को छू रही है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जरिए महिलाओं को गैस सिलिंडर देना, जनधन योजना के तहत खाता खुलवाना, मुस्लिम महिलाओं को लेकर तीन तलाक को कानूनी रूप से खत्म करना जैसे विधेयक ने जहां प्रधानमंत्री मोदी के कद को बढ़ाया वही महिलाओं की राजनीति में सक्रियता

एवं मतदान में अधिक हिस्सेदारी को नये पंख दिये हैं। इन योजनाओं से 20 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं, 5 करोड़ से ज्यादा स्कूलों छात्राओं और 11 करोड़ से ज्यादा कामकाजी महिलाओं को लाभ पहुंचा है।

अब महिलाएं राजनीति एवं राजनेताओं के वजूद को बनाने में महत्वपूर्ण हो गयी है। मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र व झारखंड में सत्तारूढ़ दलों की चुनावों के बाद फिर वापसी में महिला मतदाताओं की भूमिका निर्णायक रही। मध्यप्रदेश में लाडली बहन, महाराष्ट्र में माझी लाडकी बहिन व झारखंड में मंईयां सम्मान योजना इसके उदाहरण हैं। इसी तरह पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी भंडार, कर्नाटक में गृहलक्ष्मी, ओडिशा में शुभद्रा योजना तथा असम में मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना सामने आई है। यह होड़ आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों में भी नजर आ रही है। एक ओर जहां आप सरकार ने महिला वोटरों के लिये महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपये देने का वायदा किया, वहीं कांग्रेस ढाई हजार रुपये देने की योजना बना रही है। इस दिशा में भाजपा भी गंभीर है। दरअसल, दिल्ली में महिला वोटरों का प्रतिशत पुरुष वोटरों के पास पहुंच गया है। कहा जाता है कि साल 2020 के चुनावों में महिला मतदान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन जरूरत इस बात की है कि महिलाओं से जुड़ी योजनाएं एवं उन्हें दी जाने वाली मुफ्त सुविधाएं सत्ता प्राप्ति या वोट हासिल करने का स्वार्थी हथियार न होकर स्थायी प्रभाव व महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का जरिया हो।

उल्लेखनीय तथ्य है कि जब किसी राज्य में महिलाओं का विकास हुआ है तो वे अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति अधिक सजग हुई हैं। उन्हें सरकारों की मुफ्त की स्कीमें भी खूब लुभा रही हैं। एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट बताती है कि महिला केंद्रित योजना लागू करने वाले राज्यों की संख्या 19 हो गई है। जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम व कर्नाटक जैसे राज्य अग्रणी हैं। इन राज्यों में औसतन 7.8 लाख (कुल 1.5 करोड़) महिला वोटरों की संख्या में इजाफा हुआ है। केन्द्र एवं राज्यों की महिला कल्याणकारी योजनाओं के कारण महिला मतदान बढ़ा है, जिनमें 45 लाख महिलाएं साक्षरता में वृद्धि के कारण मतदाता बनी हैं, 36 लाख महिलाएं रोजगार और मुद्रा योजना की वजह से मतदान किया है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर का मालिक बनने के कारण 20 लाख महिलाएं मतदान के लिए गई थी और वहीं 21 लाख महिलाएं स्वच्छता, बिजली और पानी की पहुंच में सुधार के कारण मतदान के लिये अग्रसर हुई। चुनाव के दौरान नेताओं एवं राजनीतिक दलों के द्वारा किए गए मुफ्त सुविधाओं के वादों को केवल राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसके आर्थिक पक्ष पर भी विचार किया जाना चाहिए।

पंजाब में महिलाओं को एक हजार रुपये देने के आम आदमी पार्टी की घोषणा के बावजूद यह राशि न देना महिलाओं को ठगना है, उनके सम्मान को आघात लगाना है। अगर इन वादो के लिए राज्य के पास अपर्याप्त धन और सीमित संसाधन हैं तो ऐसे वादो से बचना चाहिए। राज्यों द्वारा चुनावी फायेद के लिए की गई मुफ्त सुविधाओं की घोषणा के लिए राजस्व जुटाना मुश्किल हो जाता है। मुफ्त की योजनाओं से राज्य का आर्थिक ढांचा कमजोर हो सकता है क्योंकि दी जाने वाली सब्सिडी का राज्य की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा। अगर कोई सत्ताधारी दल, राजनीतिक लाभ के लिये सरकारी पैसे को मुफ्तखोरी पर खर्च करते हैं, तो इससे राज्य का वित्तिय ढांचा बिगड़ सकता है। राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव के दौरान सार्वजनिक धन से मुफ्तखोरी और तर्कहीन वादे करना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए भी खतरा पैदा कर सकते हैं। मुफ्तखोरी की घोषणाएं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की धारणा के खिलाफ है क्योंकि जाहिर तौर पर हर राजनीतिक दल की सार्वजनिक धन तक पहुंच नहीं होगी। मुफ्त के वादे को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी सवाल है कि यह प्रथा कैसे नैतिक है क्योंकि यह मतदाताओं को लुभाने के लिए एक तरह से रिश्वत देने के समान है। जानकारों का मानना है कि श्रीलंका के आर्थिक पतन का कारण वहां के राजनीतिक दलो द्वारा दिए गए मुफ्त उपहार रहे हैं। हालांकि गरीबों की मदद के लिए चिकित्सा, शिक्षा, पानी और बिजली जैसी आधारभूत जरुरतों और कुछ कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन के व्यय को जायज ठहराया जा सकता है। इसी तरह महिलाओं के लिये कुछ योजनाएं रोजगार एवं आत्मनिर्भरता की दृष्टि से उपयोगी हो सकती है। लेकिन इन योजनाओं को वोट हथियाने का माध्यम बनाना लोकतंत्र के लिये शुभ नहीं है। केवल सत्ता प्राप्ति के लिए मुफ्त की राजनीति का खेल न खेलकर हमें स्वस्थ लोकतंत्र एवं उज्ज्वल चरित्र को बढ़ावा देना चाहिए। वोट पाने की खातिर लोकतंत्र की आत्मा को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए।

सोनमर्ग और लद्दाख को जोड़ने वाली सुरंग

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में एक लंबी सुरंग का उद्घाटन किया है। यह सुरंग सर्दियों में बर्फ से ढके रहने वाले इलाके तक साल भर जाना संभव बनाएगी। करीब 93.2 करोड़ डॉलर की लागत वाली इस परियोजना के जरिए भारत कश्मीर को लद्दाख से सीधे जोड़ना चाहता है। इसमें एक और सुरंग के साथ ही ऊंचे पहाड़ी इलाके में कई पुल भी बनाए जाने हैं। लद्दाख के इस इलाके में भारत के साथ ही पाकिस्तान और चीन की सीमा भी लगती है। बीते दशकों में यहां कई बार सीमाई विवाद सामने आते रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर के सोनमर्ग पहुंचे और 6.5 किलोमीटर लंबी इस सुरंग का उद्घाटन किया। सोनमर्ग कश्मीर घाटी के खत्म होने और लद्दाख के शुरू होने वाली जगह पर मौजूद है। यहीं से थोड़ा आगे जा कर लद्दाख

का जोजिला दर्रा शुरू होता है। इसी के नाम पर इस सुरंग को जेड मोड़ कहा जा रहा है। इस इलाके में पहली बार अब सड़क मार्ग से पूरे साल जाना संभव हो गया है। दूसरी सुरंग करीब 14 किलोमीटर लंबी है जो जोजिला दर्रे से गुजर कर सोनमर्ग और लद्दाख को जोड़ेगी। इसके साल 2026 तक तैयार हो जाने की उम्मीद है। सोनमर्ग और लद्दाख में भारी हिमपात होता है और इसकी वजह से यह दर्रा बंद हो जाता है। एसे में ये इलाके आसपास के शहरों से हर साल करीब छह महीने के लिए कटे रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच ही एक सभा को भी संबोधित किया। भारी ठंड के बावजूद इसमें सैकड़ों लोग जमा हुए थे। मोदी ने कहा कि यह विशाल परियोजना सड़क मार्ग से संपर्क बढ़ाएगी और इलाके में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस कार्यक्रम में कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह और मोदी कैबिनेट के कई सदस्य भी मौजूद थे। विशेषज्ञों का कहना है कि सुरंग की परियोजना सेना के लिए भी काफी अहम है। सेना के लिए अब लद्दाख में पहुंचना और काम करना आसान होगा। इसके साथ ही आमलोगों को भी कश्मीर घाटी से लद्दाख जाने में पूरे साल काफी सुविधा होगी। 2020 में भारत और चीन के सैनिकों की लद्दाख में झड़प हुई थी। हालांकि पिछले साल अक्टूबर में दोनों देश विवादित इलाकों में सैनिकों के गश्त को लेकर एक समझौते पर पहुंच गए थे। दोनों देशों ने अपने मोर्चों पर दसियों हजार सैनिक तैनात कर रखे हैं। अक्टूबर में कुछ बंदूकधारियों ने इस परियोजना में काम कर रहे सात लोगों को गोली मार कर उनकी जान ले ली थी। इस हमले में पांच लोग जख्मी भी हुए थे। पुलिस का आरोप है कि इलाके में कई दशकों से भारतीय शासन का विरोध कर रहे चरमपंथियों ने इसे अंजाम दिया था। 2019 में भारत ने कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया था। इसके साथ ही इस राज्य को दो हिस्सों में बांट दिया। लद्दाख को जम्मू -कश्मीर से अलग कर दिया गया और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। भारत के इतिहास में पहली बार किसी राज्य को केंद्रशासित प्रदेश बनाने की घटना तब हुई थी।

दिल्ली चुनाव में झुग्गीवासी क्यों हैं इतने अहम

साहिबा खान

दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं। दिल्ली में तीन बड़ी पार्टियां- बीजेपी, कांग्रेस और आप, वोटरों को रिझाने के लिए कई मुद्दे उठा रही हैं जिनमें से एक बड़ा मुद्दा है झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को पक्के घर और बाकी नागरिक सुविधाएं मुहैया कराना।

रविवार को शकूर बस्ती में एक चुनावी सभा में आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविन्द केजरीवाल ने इसी मुद्दे पर कहा कि बीजेपी नेता अमित शाह एफिडेविट पर हस्ताक्षर करके देते हैं कि वो दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले सभी लोगों को मकान दे सकेंगे, तो वो (केजरीवाल) चुनाव ही नहीं लड़ेंगे।

यह मुद्दा दिल्ली चुनाव में इतना जरूरी इसलिए बन गया है क्योंकि झुग्गीवासी दिल्ली में एक बहुत बड़ा वोटबैंक हैं। दिल्ली में कुल 675 झुग्गियां हैं और 1700 झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर यानी वो इलाके जिनमें झुग्गियों के छोटे छोटे पॉकेट,और कई अनधिकृत कॉलोनियां। इन झुग्गी झोपड़ियों में 15 लाख से ज्यादा वोटर हैं। झुग्गीवासी दिल्ली के कुल मतदाताओं का 10वां हिस्सा हैं और इसलिए सभी पार्टियां उन्हें अपनी ओर खींचना चाह रही हैं।

आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो इन 15 लाख से ज्यादा वोटरों में से लगभग 10 लाख लोग असल में वोट करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस अखबार से बातचीत में दिल्ली बीजेपी महासचिव विष्णु मित्तल ने बताया है कि इनमें से लगभग 7 लाख वोट आम आदमी पार्टी को जाते हैं, 2 लाख वोट बीजेपी और बचे हुए कांग्रेस और अन्य पार्टियों को। अगर इस बार बीजेपी और 2-3 लाख वोटरों को अपनी ओर ले आई तो खेल पलट सकता है। इन इलाकों में रहने वाले लोग ना केवल

बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं, बल्कि सबसे बड़ी चिंता है उनके घरों की कानूनी स्थिति। झुग्गियों पर अवैध होने के आरोप लोगों में डर और चिंता की स्थिति बनाए रखते हैं। आए दिन झुग्गियों को ढहाने की मांगें उठती रहती हैं।

2024 में, जी20 शिखर सम्मेलन से पहले, राजधानी के कई हिस्सों में अवैध निर्माणों को तोड़ने के अभियान चलाए गए थे। इनमें तुगलकाबाद, गोविंदपुरी और सुंदर नगर जैसे इलाकों में कई झुग्गियां हटाई गई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2020 में जब रेलवे के बगल में लगी हजारों झुग्गियों को हटाने की बात कही थी तब भी झुग्गीवासियों में हड़कंप मच गया था।

आम आदमी पार्टी (आप) ने दावा किया है कि उसने पहले ही कई झुग्गीवासियों को पुनर्वास और आवासीय सुरक्षा दी है। दिल्ली के पहले इन-सीटू पुनर्विकास परियोजना में, जहां दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने नेहरू कैंप, नवजीवन कैंप और भूमिहीन कैंप के झुग्गीवासियों को फ्लैट दिए हैं, वहां लगभग 8,000 झुग्गी परिवारों में से 2,000 परिवारों को आवास मिल चुका है। आप पार्टी के लिए यह पुनर्वास बड़ी भूमिका निभाएगा।

वहीं, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और कांग्रेस दोनों ही अपने-अपने चुनावी घोषणापत्र में झुग्गीवासियों के लिए पुनर्वास योजना की बात कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों में जब बीजेपी ने दिल्ली की सातों सीटें अपने नाम की थीं उसी समय उन्होंने झुग्गीवासियों के लिए 'झुग्गी विस्तारक योजना का ऐलान भी किया था। कांग्रेस के राहुल गांधी भी जल्द ही 'जय बापू, जय भीम, जय संविधान नाम के डोर टू डोर अभियान से झुग्गीवासियों के बीच अपना खाता खोलने की तैयारी में लगे हुए हैं।

आम आदमी पार्टी कहती है कि उन्होंने हजारों झुग्गीवासियों को पुनर्वास कराया है, वहीं बीजेपी इन दावों को झूठा मानती है। बीते रविवार अरविंद केजरीवाल ने शकूर बस्ती की रैली में कहा कि भारतीय रेलवे ने शकूर बस्ती पर बनने वाले एक प्रोजेक्ट का टेंडर पारित किया है। इसका खंडन करते हुए उत्तर रेलवे ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर ट्वीट कर बताया कि इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है और ऐसा कोई भी टेंडर पारित नहीं किया गया है।

आप ने इस मुद्दे पर दिल्ली उपराज्यपाल सक्सेना पर भी निशाना साधा और कहा कि वे दिल्ली में जमीन के कानूनों में बदलाव ला रहे हैं ताकि वहां विध्वंस आसान हो जाए। इन दावों को झूठा बताते हुए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पूर्वी दिल्ली में एक रैली में कहा कि आम आदमी पार्टी ने नरेला में राजीव आवास योजना के तहत आने वाले करीब 50,000 फ्लैट खाली छोड़ दिए हैं जहां झुग्गीवासियों का पुनर्वास कराना था।

खगोलीय चमत्कारों और बौद्धिक मंथन का केंद्र भी है महाकुंभ

जयसिंह रावत

महाकुंभ मेला, जिसे मानव सभ्यता के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजनों में गिना जाता है, न केवल आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक विविधता का उत्सव है, बल्कि खगोलीय चमत्कारों और बौद्धिक मंथन का केंद्र भी है। यह आयोजन हर 12 वर्षों में होता है और खगोल विज्ञान, ज्योतिष, तथा धर्मशास्त्र के अद्भुत सामंजस्य को प्रदर्शित करता है।

महाकुंभ की तिथियों का निर्धारण खगोलीय घटनाओं के आधार पर किया जाता है। यह तब आयोजित होता है जब बृहस्पति ग्रह कुम्भ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मकर राशि में होता है। यह खगोलीय स्थिति गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करती है।

महाकुंभ के खगोलीय चमत्कारों में बृहस्पति और सूर्य की स्थिति प्रमुख भूमिका निभाती है। जब बृहस्पति कुम्भ राशि में होता है, तो यह स्थिति पूरे ब्रह्मांड में विशेष ऊर्जा का संचार करती है। ज्योतिष के अनुसार, यह समय आध्यात्मिक साधना के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इसी दौरान सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना इसे और भी शुभ बना देता है।

इन घटनाओं का संयोग जल के शुद्धिकरण और ऊर्जा को सक्रिय करने में सहायक होता है। महाकुंभ में खगोलीय चमत्कारों का महत्व इस बात में निहित है कि यह आयोजन ब्रह्मांडीय ऊर्जा और मानव चेतना के बीच संबंध को उजागर करता है।

महाकुंभ के आयोजन का समय सूर्य और चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। यह दर्शाता है कि प्राचीन भारतीय खगोलशास्त्रियों ने सौर और चंद्र चक्रों का गहन अध्ययन किया था। नक्षत्रों की गति और उनके द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का अध्ययन कर यह सुनिश्चित किया जाता था कि संगम स्थल पर विशेष ऊर्जा का प्रवाह हो। बृहस्पति, सूर्य, और चंद्रमा की विशेष स्थिति को आधार बनाकर

यह आयोजन तय होता है, जो प्राकृतिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय करता है।

महाकुंभ के आयोजन में प्राचीन भारतीय खगोलविदों और ज्योतिषियों द्वारा विकसित सटीक गणनाओं का प्रयोग होता है। वैदिक ज्योतिष और खगोल विज्ञान के अनुसार, इन तिथियों का निर्धारण सौर, चंद्र, और ग्रहों की गति के आधार पर किया जाता है। यह दर्शाता है कि हमारे पूर्वज खगोल विज्ञान के गहन ज्ञान से परिचित थे।

खगोलीय गणनाओं का आधार सौरमंडल में ग्रहों की कक्षाओं, चंद्रमा के चक्र और सूर्य की गति को समझने पर निर्भर करता है। भारतीय खगोलविद, जैसे आर्यभट और वराहमिहिर, ने खगोलीय घटनाओं को मापने के लिए जटिल गणनाएं विकसित की थीं। पंचांग की रचना और महाकुंभ जैसी तिथियों का निर्धारण इन्हीं गणनाओं से संभव हुआ।

इन गणनाओं में ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। बृहस्पति का प्रभाव, जो गुरु ग्रह है, इसके कुम्भ राशि में प्रवेश करने से आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह तीव्र होता है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश सूर्य की ऊर्जा को संगम क्षेत्र में केंद्रित करता है। चंद्रमा की स्थिति ज्वार-भाटा और ऊर्जा के प्रवाह को प्रभावित करती है, जिससे संगम का जल अधिक पवित्र और ऊर्जावान माना जाता है।

प्राचीन खगोलविद न केवल खगोलीय घटनाओं का समय निर्धारण करते थे, बल्कि इन घटनाओं का स्थान और भूगोल पर प्रभाव भी समझते थे। महाकुंभ का स्थान और समय दोनों ही विशेष ऊर्जा की उपस्थिति को सुनिश्चित करते हैं। महाकुंभ के समय खगोलीय घटनाएं न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से, बल्कि भौतिक और जैविक प्रभावों के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण हैं।

इस समय पृथ्वी और ग्रहों की स्थिति में आने वाले परिवर्तन मानव शरीर और मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इन खगोलीय घटनाओं के दौरान पृथ्वी का चुम्बकीय क्षेत्र सक्रिय होता है, जिससे संगम क्षेत्र में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। खगोलशास्त्रियों का मानना है कि इस दौरान ध्यान, योग, और साधना के माध्यम से मनुष्य अपनी चेतना को ऊंचे स्तर पर ले जा सकता है।

महाकुंभ में खगोल विज्ञान और परंपराओं का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। वैदिक काल से ही खगोलशास्त्र भारतीय परंपराओं का हिस्सा रहा है। सूर्य, चंद्रमा, और अन्य ग्रहों की गति का अध्ययन कर धार्मिक अनुष्ठानों और त्योहारों का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ में स्नान का महत्व खगोलीय घटनाओं से सीधे जुड़ा है। मान्यता है कि खगोलीय ऊर्जा संगम के जल को पवित्र बनाती है और उसमें स्नान करने से पापों का नाश होता है।

खगोलीय स्थितियों के आधार पर ध्यान और साधना की विधियों को तय किया जाता है, जिससे मनुष्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ सके। महाकुंभ के दौरान खगोलीय चमत्कारों का प्रभाव केवल आध्यात्मिकता तक सीमित नहीं है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि खगोलीय घटनाओं का प्रभाव मानव शरीर पर भी पड़ता है। इस दौरान पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और ग्रहों के बीच उत्पन्न ऊर्जा मानव शरीर के जैविक कार्यों को भी प्रभावित करती है।

वैज्ञानिकों का मानना है कि खगोलीय घटनाओं के कारण जल के अणु अपनी संरचना बदलते हैं, जिससे संगम का पानी और अधिक शुद्ध और ऊर्जावान बन जाता है। महाकुंभ में जल का यह शुद्धिकरण इसे पवित्रता और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण बनाता है। महाकुंभ के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पक्ष भी खगोलीय चमत्कारों से जुड़े हैं।

मध्यप्रदेश के धार्मिक नगरों की पवित्रता बनाए रखने की सराहनीय पहल

कृष्णमोहन झा

लगभग सवा साल पहले मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री पद की बागडोर संभालने के तत्काल बाद से ही मोहन यादव ने एक के बाद एक कई सख्त फैसले लेकर यह स्पष्ट संकेत दे दिए थे कि उनकी कार्यशैली के बारे में किसी को भी कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। यह सिलसिला पिछले सवा साल से अनवरत रूप से जारी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के बारे में एक बात और निश्चित रूप से कहीं जा सकती है कि उनके कठोर फैसले भी उनके सात्विक आचार विचार को प्रतिबिंबित करते हैं ।

मध्यप्रदेश में धार्मिक स्थलों के आसपास वाले जिलों में शराब की बिक्री को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने की उन्होंने जो सराहनीय पहल की है उसका मूल्यांकन भी इसी दृष्टि से किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री की इस स्तुत्य पहल ने उन्हें भूरि भूरि प्रशंसा का हकदार बना दिया है और अब तो यह मांग भी उठने लगी है कि मुख्यमंत्री को संपूर्ण प्रदेश में शराब की बिक्री को प्रतिबंधित करने की दिशा में गंभीरता से विचार करना चाहिए।

इसमें दो राय नहीं हो सकती कि मुख्यमंत्री ने धार्मिक स्थलों में शराबबंदी को लेकर राज्य सरकार की आबकारी नीति में संशोधन के जो संकेत दिए हैं उसमें उन्हें समाज के हर वर्ग का भरपूर समर्थन मिलने में किंचित मात्र भी संदेह की गुंजाइश नहीं है।मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आगामी एक अप्रैल अर्थात नये वित्तीय वर्ष से इस संबंध में नयी नीति पर अमल किया जा सकता है। मुख्यमंत्री का मानना है कि सरकार धार्मिक स्थलों की पवित्रता अक्षुण्ण होनी चाहिए।

निकट भविष्य में राज्य के जिन धार्मिक नगरों में शराबबंदी लागू करने पर गंभीरता से

विचार किया जा रहा है उनमें उज्जैन (महाकालेश्वर मंदिर),अमरकंटक (नर्मदा उदगम स्थल) , महेश्वर(नर्मदा नदी के किनारे प्राचीन मंदिर) ओरछा (रामराजा मंदिर) ओंकारेश्वर (ज्योतिर्लिंग), मंडला (नर्मदा घाट), मुलताई (ताप्ती नदी) , दतिया(पीताम्बरा पीठ) जबलपुर (नर्मदा घाट) , चित्रकूट(रामघाट) ,मैहर (शारदादेवी मंदिर) , सलकनपुर(बीजासन मंदिर) मंडलेश्वर (नर्मदा घाट), मंदसौर(पशुपतिनाथ मंदिर) ,बरमान(नर्मदा घाट) और पन्ना(जुगल किशोर मंदिर) शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि साधु संतों ने शराब के कारण धार्मिक स्थलों की पवित्रता प्रभावित होने से रोकने के लिए इन धार्मिक नगरों में शराबबंदी लागू करने हेतु अनुरोध किया था , सरकार उनके सुझावों पर अमल करते हुए जल्द ही धार्मिक नगरों में शराबबंदी का फैसला कर सकती है। मुख्यमंत्री के अनुसार सरकार के इस फैसले से होने वाले राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए इन नगरों की सीमाओं के बाहर शराब दुकानें खोलने की अनुमति देने के बारे में आबकारी अधिकारी मंथन कर रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में मध्यप्रदेश के दो पड़ोसी राज्यों बिहार और गुजरात में शराबबंदी लागू है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल में ही जब यह बयान दिया था कि नशा नाश का कारण बनता है तभी से वहां भी शराब बंदी लागू किए जाने की अटकलें लगाई जाने लगी हैं यद्यपि इस बारे में अभी कोई ठोस फैसला नहीं किया गया है।

गौरतलब है मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी राज्य में शराबबंदी की मांग करती रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने जब नर्मदा सेवा यात्रा निकाली थी तब उन्होंने भी नर्मदा नदी के तटीय क्षेत्रों में 6 किलोमीटर की सीमा के अंदर शराब और मांस की दुकानें बिक्रीपर रोक लगाने की घोषणा की थी । यहां भी विशेष उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गत वर्ष सितंबर में अधिकारियों को पवित्र नर्मदा नदी के तट पर बसे धार्मिक नगरों में शराब और मांस की बिक्री एवं सेवन पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए थे।

मुख्यमंत्री के नये आदेश को गत वर्ष सितंबर में दिये गये उनके आदेश के विस्तारित रूप में देखा जा रहा है। सितंबर में उन्होंने पवित्र नर्मदा नदी के तटीय इलाकों में शराब और मांस की बिक्री और सेवन रोकने के आदेश दिए थे और अब मुख्यमंत्री ने उसका दायरा बढ़ाते हुए राज्य के 17 धार्मिक नगरों में शराबबंदी लागू करने की मंशा व्यक्त की है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पिछले सवा साल में जिस तरह न केवल सख्त फैसले लिए हैं बल्कि उनका क्रियान्वयन भी सुनिश्चित किया है उसे देखते हुए यह माना जा सकता है कि अब वह दिन दूर नहीं जब मध्यप्रदेश के सभी धार्मिक नगरों में शराबबंदी को सख्ती से लागू कर सरकार उन धार्मिक नगरों की पवित्रता को बनाए रखने में कोई कसर बाकी नहीं रखेगी।

देसी नहीं इस बार कोरियन खिचड़ी खाकर रहें फिट

क्या किसी टीवी शो में खिचड़ी को देखकर आप इतना टेंप्ट हो सकते हैं कि उसे बनाने के बारे में सोचें? नहीं न... पर मैं हुई थी, जब मैंने कोरियन ड्रामा देखा था। वैसे तो हर कोरियन ड्रामा देखने के बाद, उसमें दिखाई गई डिशेज को खाने का मेरा बड़ा मन करता है, लेकिन यह कुछ अलग था। खिचड़ी कोई कैसे इतनी टेंप्टिंग बना सकता है कि उसे देखकर ही खाने का मन कर जाए। इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा में सिर्फ लीड एक्टर्स की ही केमिस्ट्री आपको पसंद नहीं आएगी, बल्कि इसके अलावा बहुत चीजें हैं जो आपको ड्रामा से बांधकर रखेंगी। उन्हीं में से एक ही, शो में दिखाई गई तमाम खाने-पीने की चीजें।

जिस डिश ने मेरा सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो खिचड़ी थी। दरअसल, शो में एक सीन है जहां एक्टर की तबीयत खराब हो जाती है। तब लीड एक्ट्रेस उससे मिलने आती है। वो देखती है कि एक्टर बुखार में तप रहा है। वो उसकी दवा करके उसके लिए एक लाइट मील बनाती है, जो दक जुक है यानी खिचड़ी। मैंने इस रेसिपी को जब देखा था, तो मेरा बड़ा मन किया था कि इसे ट्राई करूं। ट्राई किया भी तो और अब मैं कभी-कभी इसी रेसिपी को बनाती हूं। यह शो बीते दिनों फिर से देखा, तो सोचा आपके साथ भी इस रेसिपी को शेयर करूं। इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊं। आइए इस आर्टिकल में और हमारी के-ऑब्सेस्ड सीरीज में आपको एक नई और लोकप्रिय डिश के बारे में बताएं।

क्या है जुक?

जैसे हमारे यहां खिचड़ी बनती है। कोरिया में भी चावल की खिचड़ी बनाई जाती है, जो कई सारे फॉर्म्स में तैयार की जाती है। इसमें तरह-तरह की सब्जियां डाली डा सकती है। वहीं, इसे चिकन के साथ भी बनाया जाता है। इसके टेक्सचर भारतीय खिचड़ी की तरह ही सॉफ्ट होता है और फ्लेवर भी अन्य कोरियन डिशेज से काफी हल्का होता है। सब्जियों से तैयार इस रेसिपी में चिकन के टुकड़ों भी डाला जाता है। यह एक हल्की और हेल्दी मील होती है, जो आपके शरीर को पूरा पोषण देती है। इसे बनाने से पहले चावलों को तेल में कुछ देर के लिए सॉते किया जाता है और फिर ब्रॉथ इसमें डाला जाता है। यह आपको इटैलियन रिजॉतो की तरह लग सकता है।

दकजुक बनाने के लिए सामग्री

- 1 कप छोटे चावल
- 500 ग्राम चिकन
- 5-6 लहसुन
- 1 छोटा इंच टुकड़ा अदरक
- 2 हरे प्याज
- 1 बड़ा चम्मच तिल का तेल
- 1 छोटी गाजर, बारीक कटी हुई
- 1 छोटा प्याज, बारीक कटा हुआ
- 1 जुकिनी, बारीक कटी हुई
- नमक स्वादानुसार

दकजुक बनाने का तरीका

- **सबसे पहले चावलों को साफ करके 3-4 बार धो लें और फिर एक कटोरे में 1 घंटे के लिए भिगोकर रख दें।**
- **अब एक बड़े पतीले में 4 कप पानी डालकर उसे गर्म करने के लिए रख दें। जब पानी में एक उबाल आ जाए, तो उसमें लहसुन, अदरक, हरा प्याज डालकर धीमी आंच पर पका लें। इसे ढककर कम से कम 30 मिनट के लिए पकाएं।**
- **30 मिनट बाज टिकन को अलग निकाल लें और फिर पानी को छानकर अलग रख लें।**
- **अब एक कुकर में तेल गर्म करें और उसमें चावल को छानकर डालें। इसे धीमी आंच पर 3-4 मिनट के लिए अच्छी तरह से सॉते करें। अब इसमें गाजर, प्याज और जुकिनी डालकर भूनें। जब सब्जियां सॉफ्ट हो जाएं, तो उसमें नमक डालकर अच्छी तरह हिलाएं और फिर ढककर 2 मिनट पकाएं।**
- **इसमें 1 लीटर ब्रॉथ डालें और अच्छी तरह से मिक्स करें। इसे एक बार सिमर होने दें और फिर तब तक पकने दें, जब तक खिचड़ी सॉफ्ट और गाढ़ी नहीं हो जाती।**
- **चिकन को अच्छी तरह से श्रेड कर लें। उसकी हड्डियां निकालकर फेंक दें। अब गाढ़ी हुई खिचड़ी में थोड़ा सा ब्रॉथ और डालें। इसमें हरा प्याज, लहसुन और श्रेडेड चिकन डालकर मिक्स करें और 4-5 मिनट और पकाएं।**
- **आखिर में ऊपर से तिल डालकर गार्निश करें और गर्मागर्म पौष्टिक खिचड़ी का मजा लें। सर्दियों में यह लाइट मील एक भरपूर भोजन का काम करेगी और आपको स्वस्थ रखेगी।**
- **अगर आप इसमें चिकन न डालना चाहें, तो इसे बिना चिकन के खूब सारी सब्जियों के साथ बना सकते हैं।**

बीमा प्रीमियम कैलकुलेटर करेगा निर्णय की सही गणना

घर के हिसाब को सही रखने के लिए
साधारण कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया ही होगा, अब बीमा का सही हिसाब बीमा प्रीमियम कैलकुलेटर से जांच लें। बीमा प्रदाता के माध्यम से दी गई जानकारी सही है या नहीं, इसका आकलन आप स्वयं से भी कर सकते हैं, बस इसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए बीमा प्रीमियम कैलकुलेटर की। तो जानिए कैसे ये आपके लिए मददगार है और साथ ही कैसे आप इसे स्वयं भी जांच सकते हैं।

क्या है बीमा प्रीमियम कैलकुलेटर

बीमा प्रीमियम कैलकुलेटर आपके बीमा प्रीमियम की गणना करने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए ऑनलाइन उपकरण हैं। ये जीवन बीमा प्रदाताओं की तरह ही कार्य करते हैं। हालांकि बीमा प्रीमियम कैलकुलेटर पहले से ही तैयार किए गए ऑनलाइन फॉर्मूले पर काम करते हैं। और इस कैलकुलेटर पर आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी और विवरण के आधार पर ही सारी गणना की जाती है। इस गणना को बस कुछ ही मिनटों में पूरा करते ही उपयुक्त परिणाम आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगते हैं।

क्या होगा फ़ायदा

किसी घर को ख़रीदने से पहले हम ये जांचते हैं कि घर जिस क्षेत्र में है वहां बाक़ी की ज़मीन का रेट इतना ही है जितने का हम ले रहे हैं या नहीं, घर को मरम्मत की ज़रूरत तो नहीं है आदि। इस तरह प्राप्त जानकारी के आधार पर ही हम ये तय करते हैं कि वहां घर ख़रीदेंगे या नहीं। ठीक इसी प्रकार किसी भी बीमा पॉलिसी को लेने से पहले प्रीमियम कैलकुलेटर की मदद से गणना का विवरण प्राप्त किया जा सकता है। इसे एक प्रीमियम उद्धरण या कोटेशन (लिखित रूप में प्राप्त किया गया प्रीमियम का अनुमान) तैयार किया जाता है जिसे आप अपनी पॉलिसी पर भुगतान कर सकते हैं। यह जीवन बीमा प्रदाताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली गणना के समान ही है जो आपकी पॉलिसी प्रीमियम को निर्धारित करते हैं। हालांकि, इस प्रीमियम कैलकुलेटर का उपयोग करना आसान है, जिसके चलते आपको प्रीमियम की मैन्युअल गणना करने के ज़रूरत नहीं होती। किसी प्रकार की बीमा योजना की तलाश करते समय प्रीमियम कोटेशन काफ़ी फायदेमंद हो जाता है। इस स्थिति में आप कोटेशन के आधार पर लागत, लाभ आदि के बारे में विश्लेषण कर सकते हैं। और अपनी पसंद के अनुसार पॉलिसी का चयन कर सकते हैं। साथ ही कौन-सी पॉलिसी आपके लिए बेहतर रहेगी इसके लिए ऑनलाइन ही अन्य कंपनियों से तुलना भी करके एक बेहतर विकल्प चुन सकते हैं।

ऐसे करें गणना

- जिस भी संस्था से आप बीमा ले रहे हैं उसकी वेबसाइट को खोलें। कैलकुलेटर वाले विकल्प को चुनें। अब आप जिस भी योजना के लिए बीमा ले रहे हैं उसे चुनें।
- इसके बाद रिक्त स्थानों में भरी जाने वाली जानकारी या विवरण लिखें जैसे कि आपका नाम, जन्म तिथि, लिंग, फोन नंबर और ईमेल आईडी आदि।
- इन विवरणों को पूरा करने के बाद, एक नया पेज खुलेगा जिसमें पॉलिसीधारक के रूप में आपकी वित्तीय क्षमता का आकलन किया जाएगा। इसमें आपकी वर्तमान आय, आप जिस प्रकार की पॉलिसी चाहते हैं, आप कितनी प्रीमियम राशि का भुगतान कर सकते हैं, आदि जैसे विवरण का जवाब देना होगा।
- अगल-अगल पॉलिसी के आधार पर कैलकुलेटर कुछ अन्य प्रश्न भी पूछ सकता है जैसे- यदि आप जीवन बीमा बचत योजना कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं, तो आपको तय वर्षों के बाद बचत के रूप में कितनी राशि चाहिए आदि।
- सभी प्रश्नों के उत्तर देने के पश्चात, बीमा प्रीमियम कैलकुलेटर के माध्यम से सारा विवरण आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगेगा। इससे न सिर्फ़ आप सारे विवरण को कम समय में बेहतर तरीके से समझ पाएंगे बल्कि कई अन्य प्रकार की पॉलिसी का चयन भी कर सकेंगे।

हाइपर बच्चे को कैसे संभाले

छोटे बच्चे अक्सर दूसरे बच्चों को देखकर जिद्द करते हैं। कई बच्चें बहुत ज्यादा गुस्से वाले होते हैं। इस तरह के बच्चों को कई बार सम्भालना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि उन्हें समझाने के लिए काफी मेहनत लगती है। कई बार मां-बाप बच्चों से परेशान हो जाते हैं जिसकी वजह से बच्चे और भी ज्यादा चिढ़िचढ़े होने लगते हैं। जिसकी वजह से आगे कभी बच्चों को शांत करना मुश्किल होता है।

अक्सर गुस्से में आकर माता पिता बच्चों पर हाथ उठा देते हैं, जो बड़े होकर बच्चों के लिए परेशानी का सबब बनते हैं। वो भी यही सीख लेते हैं कि किसी के गुस्से को शांत करने के लिए हाथ उठाना जरूरी है। ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं बच्चे को शांत करने के तरीकों के बारे में।

काउंटिंग

गुस्सा आने पर आप बच्चे से कहें कि वह गिनती गिनना शुरू कर दें। ऐसा करवाने के लिए आपको शुरू से ही बच्चों को ये आदत डालनी होगी। गिनती गिनना एक ऐसा तरीका है जो हमेशा काम आता है। ये बड़ों के गुस्से को कम करने में भी कामयाब होता है।

वॉक

अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा टीवी या फिर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है और आप चाहते हैं कि बच्चा इन सभी चीजों से दूर रहे तो आपको बच्चे को आराम से समझाने की जरूरत है। जैसे ही आप बच्चे को टीवी या मोबाइल चलाने से मना करते हैं तो बच्चे गुस्सा हो जाते हैं ऐसे में आपको उन्हें प्यार से समझाने की जरूरत है। साथ ही उसके अलावा उन्हें पार्क में जाकर वॉक या फिर नेचर के बारे में बताएं। कुछ ऐसी चीज को बताएं जिससे आपका बच्चा आपकी बातों में इंटरेस्ट दिखाने लगे।

बच्चों की बात सुनें

गुस्सा किसी को भी आ सकता है और आपको इस बात को समझने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के गुस्से को शांत किया जाए तो आप बच्चों को समझाने से पहले उसकी बात को सुनें। बच्चे को सुनना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से बच्चे को अपनी जरूरत का एहसास होता है।

बच्चे को दें स्पेस

बच्चा चाहें छोटा हो या बड़े गुस्सा होने पर वह अपने पसंदीदा स्पॉट पर बैठता ही है। ऐसे में बच्चों को उसके चिलिंग स्पॉट में बैठने दें और फिर थोड़ी देर बाद आप उस जगह पर जा सकते हैं और अपने बच्चे को समझाने की कोशिश करें।

सहानुभूति

कई माता-पिता की आदत होती है कि वह हर चीज में बच्चे को कोसने लगते हैं और उसकी गलतियां निकालते हैं। ऐसा करने से बच्चों में गुस्सा बढ़ता है और वह जिद्दी हो जाते हैं। ऐसा करने से अच्छा है कि आप अपने बच्चे की बात सुनें और समझाएं। इससे आपके बच्चे के दिल में सहानुभूति की भावना बढ़ती है।

सीड ट्रे से सीडलिंग को कब करें ट्रांसप्लांट

जो भी गार्डनर बीजों से पौधों को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, वे अक्सर सीड्स को सीड ट्रे में बोना पसंद करते हैं। इससे वे एक साथ कई बीज बो पाते हैं। साथ ही साथ, सीड ट्रे के कारण नमी और तापमान को नियंत्रित करना अधिक आसान हो जाता है। जिससे बीज जल्दी अंकुरित हो पाते हैं। लेकिन एक बार जब बीज अंकुरित हो जाते हैं, तो फिर उन्हें बढ़ने के लिए अधिक स्पेस की जरूरत होती है। ऐसे में अगर उसे सीड ट्रे में ही छोड़ दिया जाए तो इससे उनकी ग्रोथ पर विपरीत असर पड़ता है और उन्हें पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। हालांकि, अधिकतर लोगों को इस बात का पता ही नहीं होता है कि सीड ट्रे से सीडलिंग को कब ट्रांसप्लांट करना चाहिए।

डेवलपमेंट पर दें ध्यान

अगर आप सीडलिंग को सीड ट्रे से ट्रांसप्लांट करने का मन बना रहे हैं तो ऐसे में पहले आपको उसकी डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए। सीडलिंग का साइज और उसकी ग्रोथ से आपको यह पता चल जाएगा कि ट्रांसप्लांट करना सही है या नहीं। आपको सीडलिंग को तब तक ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहिए, जब तक कि उस पर पत्तियां ना आ जाएं। आपको यह समझना चाहिए कि सीडलिंग पर नजर आने वाली पहली पत्तियां वास्तव में सीड लीव्स होती हैं। आपको इसके बाद ही ट्रांसप्लांट करना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि सीडलिंग ट्रांसप्लांटेशन स्ट्रेस को आसानी से हैंडल कर सकती हैं।

साइज पर दें ध्यान

सीडलिंग की ग्रोथ के साथ-साथ उनके साइज पर भी ध्यान दिया जाना उतना ही महत्वपूर्ण है। हमेशा ध्यान रखें कि आप सीडलिंग को तभी ट्रांसप्लांट करें, जब आपके छोटे पौधों की लंबाई लगभग 4 से 8 इंच के बीच हो जाए। इस दौरान उन्हें ट्रांसप्लांट करने से वे ट्रांसप्लांटिंग शॉक को हैंडल कर पाते हैं।

रूट सिस्टम पर दें ध्यान

कभी भी सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करने से पहले रूट सिस्टम पर खासतौर पर ध्यान देना चाहिए। आप पहले सीडलिंग के रूट्स को चेक करें। अगर रूट्स सीड्स ट्रे में गुच्छे में नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि रूट सिस्टम अच्छी तरह डेवलप हो गया है। इस दौरान सीडलिंग को बिना किसी परेशानी के ट्रांसप्लांट किया जा सकता है।

मौसम पर दें ध्यान

सीडलिंग को सीड्स ट्रे से ट्रांसप्लांट करते समय मौसम पर विशेष ध्यान दिया जाना बेहद महत्वपूर्ण है। हमेशा आप पौधे की मौसम संबंधी जरूरतों को समझें और फिर मौसम का मिजाज देखें। अगर मौसम अनुकूल होता है तो इससे सीडलिंग पर ट्रांसप्लांट के दौरान अधिक स्ट्रेस नहीं आता है। कोशिश करें कि आप अत्यधिक गर्मी या तेज़ हवाओं के दौरान ट्रांसप्लांटिंग ना करें।

प्लेस पर दें ध्यान

ट्रांसप्लांटिंग से पहले आपको यह भी समझना चाहिए कि आपका प्लांट बाहरी मौसम की मार को झेलने के लिए तैयार है या नहीं। मसलन, अगर आपने इनडोर सीडलिंग शुरू की है तो आपको उन्हें ट्रांसप्लांट से पहले धीरे-धीरे उन्हें बाहरी मौसम के अनुकूल बनाएं। इस प्रोसेस को हार्डनिंग ऑफ के रूप में जाना जाता है, जिसकी मदद से सीडलिंग को तापमान, प्रकाश और हवा में होने वाले बदलाव के साथ खुद को एडजस्ट करने में मदद मिलती है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

सोनिया ने कांग्रेस के नए मुख्यालय का उद्घाटन किया

नईदिल्ली। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने बुधवार को पार्टी के नए मुख्यालय 'इंदिरा भवन' का उद्घाटन किया। पिछले करीब पांच दशक से पार्टी का मुख्यालय '24 अकबर रोड' था। अब मुख्य विपक्षी दल का नया मुख्यालय '9ए कोटला मार्ग' पर बनाया गया है। सोनिया गांधी ने फीता काटकर नए भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भी मौजूद थे। इससे पहले, कांग्रेस मुख्यालय के प्रांगण में ध्वजारोहण किया गया और नेताओं ने राष्ट्रीय गीत, राष्ट्र गान तथा 'विजयी विश्व तिरंगा प्यारा..' गाया। 'इंदिरा भवन' को पार्टी और उसके नेताओं की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें प्रशासनिक, संगठनात्मक और रणनीतिक कार्यों में सहयोग करने के लिए आधुनिक सुविधाएं शामिल हैं। कांग्रेस के इस नए मुख्यालय का काम पिछले कई वर्षों से जारी था। कांग्रेस '24, अकबर रोड को फिलहाल खाली नहीं करेगी।

भारत को कमजोर करने वाली ताकतों के साथ कांग्रेस : नड्डा

नईदिल्ली। भाजपा ने लोकसभा के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तब हमला बोला जब उन्होंने दावा किया कि विपक्ष सिर्फ भाजपा के खिलाफ नहीं बल्कि भारतीय राज्य के खिलाफ लड़ रहा है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उन ताकतों के साथ काम करने का इतिहास रहा है जो कमजोर भारत चाहते हैं। नड्डा ने एक्स पर लिखा कि अब और छिपाया नहीं जा सकता, कांग्रेस का घिनौना सच अब उनके ही नेता ने उजागर कर दिया है। मैं राहुल गांधी को यह स्पष्ट रूप से कहने के लिए प्रशंसा करता हूं कि देश क्या जानता है- कि वह भारतीय राज्य से लड़ रहे हैं! नड्डा ने कहा कि यह कोई रहस्य नहीं है कि गांधी और उनके पारिस्थितिकी तंत्र का शहरी नक्सलियों और डीप स्टेट के साथ घनिष्ठ संबंध है जो भारत को बदनाम करना, नीचा दिखाना और बदनाम करना चाहते हैं। उनकी बार-बार की हरकतों ने भी इस विश्वास को मजबूत किया है।

केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट से भरा नामांकन

नईदिल्ली। आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी के साथ कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना की। उन्होंने आज दिन में नई दिल्ली विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। वह अपनी पत्नी के साथ कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना करने पहुंचे थे। नई दिल्ली विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने नामांकन दाखिल कर दिया है। मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूं कि कृपया काम के नाम पर वोट करें, एक तरफ काम करने वाली पार्टी है और दूसरी तरफ गाली देने वाली पार्टी है। काम, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली के नाम पर वोट करें। पानी, सड़क, इन चीजों के लिए वोट करें। केजरीवाल ने कहा कि बहुत सारा काम किया गया है। अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि लोग कड़ी मेहनत के लिए वोट करेंगे।

दिल्ली में हम आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं : अखिलेश

लखनऊ। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस से ज्यादा मजबूत है इसलिए उनकी पार्टी ने आप के साथ खड़े होने का फैसला किया है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा के खिलाफ लड़ने वाली क्षेत्रीय पार्टी को इंडिया गठबंधन के नेताओं का समर्थन करना चाहिए। दिल्ली में आप और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप मजबूत है और हमने उनके साथ खड़े होने का फैसला किया है। सवाल दिल्ली का है और हमारा लक्ष्य है कि बीजेपी हार जाए। कांग्रेस और आप का भी एक ही लक्ष्य है। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो ने यह भी स्पष्ट किया कि इंडिया गठबंधन बरकरार है। मुझे याद है कि जब इंडिया गठबंधन बना था, तो यह निर्णय लिया गया था कि जहां भी कोई क्षेत्रीय पार्टी मजबूत होगी, गठबंधन उन्हें समर्थन देगा। इससे पहले, भाकपा के महासचिव डी राजा ने स्वीकार किया कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद इंडिया गुट विभाजित है।

दिल्ली में 5 फरवरी को खत्म हो जाएगी आप-दा सरकार : पुरी

नईदिल्ली। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आगामी दिल्ली चुनावों में भाजपा की संभावनाओं पर विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि आप-दा 5 फरवरी को भाजपा की अपेक्षित जीत के साथ समाप्त होगा। उन्होंने अपना विश्वास दोहराया कि भाजपा के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी मौजूदा सत्ता विरोधी लहर के कारण जीत हासिल करेंगे। पुरी ने अरविंद केजरीवाल की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए अधूरे वादों और कथित भ्रष्टाचार को उजागर किया। पुरी ने यमुना नदी की खराब स्थिति और दिल्ली की वायु गुणवत्ता को आम आदमी पार्टी की विफलता बताया। उन्होंने दिल्ली सरकार पर अपने नेताओं के निजी वाहनों पर अत्यधिक खर्च करने का भी आरोप लगाया और मुख्यमंत्री उम्मीदवार पर भाजपा के फैसले का वादा किया। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मैं यहां रमेश बिधूड़ी के नामांकन दाखिल करने के लिए आया हूं। यहां लोगों में उत्साह आप देख सकते हैं।

तीन नौसेना युद्धपोतों के जलावतरण के बाद बोले प्रधानमंत्री मोदी

भारत एक प्रमुख समुद्री शक्ति बन रहा है

नई दिल्ली। भारतीय नौसेना के युद्धपोतों आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरि और आईएनएस वाघशीर को बुधवार को नौसेना की गोदी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में बल में शामिल किया गया। नौसेना ने तीनों बड़े युद्धपोतों के शामिल होने को एक ऐतिहासिक अवसर करार दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत एक प्रमुख समुद्री शक्ति बन रहा है। भारत को विश्व में, विशेषकर ग्लोबल साउथ में एक विश्वसनीय और जिम्मेदार साझेदार के रूप में मान्यता मिल रही है। भारत विस्तारवाद के लिए नहीं, विकास के लिए काम कर रहा है। भारत ने हमेशा एक मुक्त, सुरक्षित, समावेशी और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र का समर्थन किया है।

इससे पहले पीएम मोदी ने कहा कि 15 जनवरी के दिन को सेना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। देश की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले प्रत्येक जांबाज को मैं नमन करता हूं। मां भारती की रक्षा में जुटे हर वीर-वीरांगना को मैं बधाई देता हूं। आज भारत की समुद्री विरासत नेवी के गौरवशाली इतिहास और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए भी बहुत बड़ा दिन है।

उन्होंने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज ने नौसेना को नया सामर्थ्य और विजन दिया था। आज उनकी इस पावन धरती पर 21वीं सदी की नेवी को सशक्त करने की तरफ हम एक बड़ा कदम उठा रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है, जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। गर्व की बात कि ये तीनों मेड इन इंडिया हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत पूरे विश्व और खासकर ग्लोबल साउथ में एक भरोसेमंद और जिम्मेदार साथी के रूप में पहचाना जा रहा है। भारत विस्तारवाद नहीं, भारत विकासवाद की भावना से काम करता

है। 21वीं सदी के भारत का सैन्य सामर्थ्य भी अधिक सक्षम और आधुनिक हो, ये देश की प्राथमिकताओं में से एक है। जल हो, थल हो, नभ हो, समुद्र की गहराई हो या फिर असीम अंतरिक्ष हर जगह भारत अपने हितों को सुरक्षित कर रहा है। इसके लिए निरंतर रिफॉर्म किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल अनेक बड़े निर्णयों के साथ शुरू हुआ है। तेज गति से हमने नई नीतियां बनाई हैं, देश की जरूरतों को देखते हुए हमने नए कार्य शुरू किए हैं, देश के हर कोने, हर सेक्टर का विकास हो, इस लक्ष्य के साथ हम चल रहे हैं। भारत वैश्विक सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और भू-राजनीतिक परिदृश्य को दिशा देने में प्रमुख भूमिका निभाने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तटीय समुद्री क्षेत्र, नौवहन की स्वतंत्रता और सुरक्षित व्यापार आपूर्ति लाइनों एवं समुद्री मार्गों की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। हमें समुद्र को नशीले पदार्थों, हथियारों और आतंकवाद से बचाने में वैश्विक साझेदार बनना चाहिए और इसे सुरक्षित एवं समृद्ध बनाना चाहिए।

दुनिया के विध्वंसक जहाजों में शुमार आईएनएस सूरत

आईएनएस सूरत 15बी श्रेणी के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट का चौथा और अंतिम जहाज है। यह दुनिया के सबसे बड़े और सबसे परिष्कृत विध्वंसक जहाजों में शुमार है। इसमें 75 फीसदी स्वदेशी सामग्री है, जो अत्याधुनिक हथियार, सेंसर पैकेज और उन्नत नेटवर्क-केंद्रित क्षमताओं से लैस है।

समुद्र में लंबे समय तक रह सकता है आईएनएस नीलगिरी

आईएनएस नीलगिरी 17ए स्टील्थ फ्रिगेट प्रोजेक्ट का पहला जहाज है। इसे भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है। इसे बढ़ी हुई क्षमता, समुद्र में लंबे समय तक रहने व स्टील्थयुक्त उन्नत सुविधाओं के साथ नौसेना में शामिल किया गया है। यह स्वदेशी फ्रिगेट की अगली पीढ़ी को दर्शाता है।

फ्रांसीसी नौसेना के सहयोग से वाघशीर का निर्माण

आईएनएस वाघशीर पी75 स्कॉर्पीन परियोजना की छठी और अंतिम पनडुब्बी है। आईएनएस वाघशीर पनडुब्बी निर्माण में भारत की बढ़ती विशेषज्ञता का प्रतिनिधित्व करती है। इसका निर्माण फ्रांस के नौसेना समूह के सहयोग से किया गया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने दोपहर के भोजन पर महायुति विधायकों से मुलाकात की

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के विधायकों से बुधवार को यहां दोपहर के भोजन पर मुलाकात की। राज्य सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि यह बैठक आईएनएस आंग्रे सभागार में हुई। सूत्रों ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार तथा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा), शिवसेना और उनके अन्य सहयोगी दलों के सत्तारूढ़ गठबंधन के अधिकांश विधायक मौजूद थे।

खरगे ने आजादी वाली टिप्पणी पर भागवत को घेरा

कहा- देश में घूमना भी मुश्किल हो जाएगा

नई दिल्ली। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की टिप्पणी की निंदा की। दरअसल, भागवत ने कहा था कि भारत को असली आजादी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन मिली। इसके साथ ही खरगे ने आरएसएस प्रमुख को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वे ऐसी ही टिप्पणियां करते रहेंगे तो उनका पूरे देश में घूमना मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन के मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि आरएसएस के लोगों को लगता है कि राम मंदिर के उद्घाटन से आजादी मिली है। उन्हें 1947 की आजादी याद नहीं है, क्योंकि उन्होंने इसके लिए लड़ाई नहीं लड़ी।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, आपको मालूम होगा कि ऐसे बयान वे ही देते हैं जिनका आजादी से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने इसके लिए लड़ाई नहीं लड़ी। मैंने आरएसएस प्रमुख का बयान पढ़ा, उन्होंने कहा कि असली आजादी राम मंदिर के उद्घाटन से मिली। उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ राम मंदिर का उद्घाटन किया था। पीएम मोदी का मानना है कि 2014 में जब वे पीएम बने तब आजादी मिली।

उन्होंने आगे कहा, आरएसएस लोगों का मानना है कि राम मंदिर के उद्घाटन से आजादी मिली। यह शर्म की बात है, हमें 1947 में आजादी मिली, लेकिन वे इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इसके लिए संघर्ष नहीं किया। जेल नहीं गए, इसलिए उन्हें यह याद नहीं है। हमें याद है, क्योंकि आजादी के लिए हमारे लोग मरे और संघर्ष किए। मल्लिकार्जुन खरगे ने मोहन भागवत की टिप्पणी की निंदा की और कहा कि अगर वे ऐसी ही टिप्पणियां करते रहेंगे तो उनका पूरे देश में घूमना मुश्किल हो जाएगा।

मल्लिकार्जुन खरगे ने बताया कि कांग्रेस

मुख्यालय उन ताकतों से लड़ने का केंद्र बनेगा जो संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रहे हैं। बाबासाहेब आंबेडकर का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जो इतिहास भूल गए हैं, वे कभी इतिहास नहीं बना सकतें। कांग्रेस नेता ने कहा, जो लोग कांग्रेस द्वारा किए गए काम को भूल गए हैं, मैं कहूंगा कि आप इतिहास बनाने में सक्षम नहीं होंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजकल पार्टियां देश के लिए काम करने के बजाय केवल कांग्रेस को गाली देने में अपना समय बर्बाद कर रही हैं।

कांग्रेस ने किया नए मुख्यालय का उद्घाटन

इससे पहले खरगे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, कांग्रेस पार्टी का नया मुख्यालय इंदिरा भवन लोकतंत्र, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी विकास और सामाजिक न्याय की नींव पर बनाया गया है। कांग्रेस के 140 साल पुराने गौरवशाली इतिहास का प्रतीक यहां की दीवारें सत्य, अहिंसा, बलिदान, संघर्ष और देशभक्ति की महान गाथा बयान करती है।

इस कार्यक्रम में मल्लिकार्जुन खरगे के अलावा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल थे। पार्टी नेताओं ने नए मुख्यालय में पार्टी का झंडा फहराया और वंदे मातरम और राष्ट्रगान गाया। इसके बाद सोनिया गांधी ने भवन का उद्घाटन किया और खरगे को भवन के प्रवेश द्वार पर रिबन काटने में अपने साथ शामिल होने के लिए कहा।

भागवत का 'सच्ची स्वतंत्रता' वाला बयान 'राजद्रोह' के समान है : राहुल

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत का यह बयान राजद्रोह के समान है कि भारत को सच्ची स्वतंत्रता राम मंदिर बनने के बाद मिली। राहुल ने पार्टी के नए मुख्यालय के उद्घाटन के अवसर पर पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि भागवत ने जो कहा है वह हर भारतीय का अपमान है और किसी दूसरे देश में ऐसा होने पर तो भागवत अब तक गिरफ्तार किए जा चुके होते।

भागवत ने सोमवार को कहा था कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि 'प्रतिष्ठा द्वादशी' के रूप में मनाई जानी चाहिए क्योंकि अनेक सदियों से दुश्मन का आक्रमण झेलने वाले देश को सच्ची स्वतंत्रता इस दिन मिली थी। राहुल गांधी ने कहा, ''भागवत ने जो कहा है वह राजद्रोह के समान है क्योंकि उनके कहने का मतलब है कि संविधान अवैध है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई अवैध है... किसी दूसरे देश में तो अब तक उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता और उन पर मुकदमा चलाया जाता।''

उन्होंने कहा कि भागवत का यह बयान हर भारतीय का अपमान है। राहुल गांधी ने कहा कि अब समय आ गया है जब इस तरह की बकवास सुनना बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा, ''दो विचारों के बीच लड़ाई है। एक हमारा विचार है जो संविधान का विचार है और दूसरी तरफ आरएसएस का विचार है जो इसके उलट है।'' कांग्रेस नेता ने कहा, ''देश में कोई दूसरा दल नहीं है जो भाजपा और आरएसएस के एजेंडे को रोक सके। सिर्फ कांग्रेस ही इन्हें रोक सकती है क्योंकि हम एक विचारधारा वाली पार्टी हैं।

खेल
प्रमुख समाचार

शुक्रवार को भारत पहुंचेगी इंग्लिश टीम

नईदिल्ली। भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 और 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। इसके लिए इंग्लिश टीम को भारत दौरे पर आना है। लेकिन उससे पहले जोस बटलर की अगुवाई में इंग्लैंड टीम अबूधाबी में ट्रेनिंग कर रही है। साकिब महमूद को वीजा मिलने में देरी के कारण ट्रेनिंग कैंप से बाहर होना पड़ा। पहला टी20 बुधवार 22 जनवरी को खेला जाएगा। इससे पहले इंग्लैंड की टीम शुक्रवार को कोलकाता पहुंचेगी। ईसीबी को उम्मीद है कि इससे पहले मामले सुलझ जाएगा। भारत के लिए वीजा मिलने में देरी पाकिस्तानी मूल के इंग्लैंड के खिलाड़ियों के लिए एक आम समस्या है।

बता दें कि, पिछले साल जब इंग्लैंड टीम भारत दौरे पर आई थी तब शोएब बशीर को वीजा मिलने में देरी के कारण हैदराबाद में इंग्लैंड के पहले टेस्ट से बाहर होना पड़ा था। 6 साल पहले वीजा प्रक्रिया में देरी के कारण महमूद को भारत दौरे के लिए इंग्लैंड लायंस की टीम से बाहर होना पड़ा था।

ईसीबी ने मामले में टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया, लेकिन माना जा रहा है कि उसे उम्मीद है कि महमूद टीम के साथ फ्लाइट में सवार होने के लिए समय पर अपना वीजा हासिल कर लेंगे। इंग्लैंड की टी20 टीम में शामिल पाकिस्तानी मूल के दो अन्य खिलाड़ियों आदिल राशिद और रेहान अहमद को पहले ही वीजा मिल चुका है।

शाकिब महमूद को भारत दौरे से पहले अबू धाबी में पेस-बॉलिंग कैंप में जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, ब्रायडन कार्स और मार्क वुडे के साथ जुड़ना था। इसकी देखरेख जेम्स एंडरसन बतौर फॉस्ट बॉलिंग कंसल्टेंट कर रहे हैं लेकिन वीजा प्रक्रिया के तहत शाकिब को अपना पासपोर्ट जमा करना पड़ा, इसलिए वे यात्रा करने में असमर्थ थे।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 225 अंक चढ़ा निफ्टी 23,213 पर बंद

नईदिल्ली। वैश्विक बाजारों से पॉजिटिव रुख के बीच घरेलू शेयर बाजार बुधवार (15 जनवरी) को लगातार ट्रेडिंग सेशन में बढ़त लेकर बंद हुए। अदाणी ग्रीन, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और एनटीपीसी जैसे एनर्जी स्टॉक्स और आईटी स्टॉक में तेजी से बाजार को सपोर्ट को मिला है। हालांकि, देसी कंपनियों के तीसरी तिमाही के नतीजे और विदेशी निवेशकों की बिकवाली को लेकर बाजार में अभी भी चिंता बनी हुई है। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स बुधवार (14 जनवरी) को 400 से ज्यादा अंक की बढ़त लेकर 76,900 अंक पर खुला। कारोबार के दौरान यह 76,479 अंक तक गिर गया। अंतिम घंटों में वापसी करते हुए सेंसेक्स 224.45 अंक या 0.29% चढ़कर 76,724.08 पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी50 भी आज मजबूती के साथ खुला। अंत में यह 23,200 का मनोवैज्ञानिक स्तर पार करते हुए 37.15 या 0.16% बढ़कर 23,213.20 पर क्लोज हुआ।

आदित्य बिरला फैशन को बोर्ड से मिली बड़ी मंजूरी

नईदिल्ली। आदित्या बिरला ग्रुप की कंपनी आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल को बोर्ड ऑफ़ डायरेकर्स की तरफ से बड़ी मंजूरी मिली है। कंपनी प्रेफरेंशियल इश्यू और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिये 1297.50 करोड़ रुपये (50 करोड़ डॉलर) जुटाएगी। आदित्य बिरला फैशन ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि बुधवार को बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स की बैठक हुई। बैठक में बोर्ड ने इक्विटी शेयरों के प्रेफरेंशियल इश्यू और क्यूआईपी के कॉम्बिनेशन के जरिये 50 करोड़ डॉलर जुटाने को मंजूरी दे दी। बयान में कहा गया, बोर्ड ने प्रोमोटर ग्रुप की इकाई पिलानी इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन को 317.45 रुपये के इश्यू प्राइस पर 10 रुपये फेस वैल्यू के 4.08 करोड़ शेयर जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे कुल 1,297.50 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे।

रुपये की गिरावट ने बढ़ाई सरकार की चिंता

नईदिल्ली। डॉलर के मुकाबले रुपये में लगातार गिरावट ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी है। इससे निपटने के लिए सरकार आगामी बजट में कुछ अहम फैसले ले सकती है। ईवाई के मुख्य नीति सलाहकार डीके श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार आगामी बजट में पिछले कुछ महीनों में रुपये के मूल्य में आई भारी गिरावट को रोकने के लिए आयात पर उच्च शुल्क लगाने पर विचार कर सकती है। प्रख्यात अर्थशास्त्री ने तर्क दिया कि उच्च आयात शुल्क से आयातकों की ओर से डॉलर की मांग पर अंकुश लगेगा और रुपये के गिरते मूल्य को रोकने में मदद मिलेगी। रुपया 13 जनवरी को 86.70 प्रति डॉलर के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया था। डीके श्रीवास्तव ने एक साक्षात्कार में कहा, ''अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में अचानक आई गिरावट नीति निर्माताओं के लिए एक चुनौती बनने जा रही है।

हल्दीराम में हिस्से खरीदने की रेस में पेप्सिको भी शामिल

नईदिल्ली। स्नैक्स और मिठाइयों की दिग्गज कंपनी हल्दीराम में अब हिस्सेदारी खरीदने की होड़ तेज हो गई है। अमेरिका की प्रमुख कंपनी पेप्सिको भी इसमें शामिल हो गई है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी के अधिकारी हल्दीराम स्नैक्स फूड में हिस्सेदारी खरीदने के लिए सीधे प्रमोटर अग्रवाल फैमिली से बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा, सिंगापुर की टेमासेक और अल्फा वेव ग्लोबल जैसी कंपनियां भी 10-15% हिस्सेदारी खरीदने की पेशकश कर चुकी हैं। सूत्रों के मुताबिक, पेप्सिको के न्यूयॉर्क मुख्यालय के अधिकारियों ने हल्दीराम में माइनोरिटी स्टेक खरीदने के लिए अग्रवाल परिवार से बातचीत शुरू कर दी है, हालांकि यह बातचीत अभी शुरुआती दौर में है और आगे नहीं बढ़ने का भी खतरा है। अगर यह डील सफल होती है, तो इसमें फंडिंग पेप्सिको की मूल कंपनी द्वारा की जा सकती है।

ट्रंप का नया कार्यकाल और बजट निर्माण

टी टी राम मोहन

आर्थिक नीति बनाते समय अनिश्चितता को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। कई बार ऐसे मौके भी आते हैं जब अनिश्चितता बहुत अधिक होती है। हाल के वर्षों में कोविड-19 महामारी सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आई। यह कहना मुश्किल था कि यह कब तक बनी रहेगी। इस पर नीतिगत प्रतिक्रिया एकदम स्पष्ट थी- राजकोषीय और मौद्रिक प्रोत्साहन। दुनिया के तमाम देशों ने भी इसके कारण अलग-अलग स्तर पर प्रोत्साहन दिया।

वित्त वर्ष 2025-26 के बजट के पहले हालात शायद और भी चुनौतीपूर्ण हैं। किसी को नहीं पता कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप अपनी योजनाओं को कैसे आगे ले जाएंगे और अन्य देशों की क्या प्रतिक्रिया होगी। यूक्रेन और पश्चिम एशिया के भूराजनीतिक हालात पर उनका रुख भी अभी स्पष्ट नहीं है। ग्रीनलैंड और पनामा नहर के रूप में उन्होंने खुद दो नई भूराजनीतिक समस्या खड़ी कर ली हैं। बस एक बात तय है- विश्व अर्थव्यवस्था को बड़े झटकों के लिए तैयार रहना होगा। आगामी आम बजट में पूरा ध्यान वृद्धि की गति बरकरार रखने पर होना चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था आने वाले किसी भी झटके से निपटने के लिए तैयार रहे।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के हालिया आंकड़ों के मुताबिक हम वित्त वर्ष 2024-25 में 10.5 फीसदी नॉमिनल वृद्धि के लक्ष्य से कुछ पीछे रह जाएंगे। मगर हम राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.9 फीसदी से कम रखने का लक्ष्य पा सकते हैं क्योंकि पूंजीगत व्यय बजट अनुमान से कम रहेगा। अगले वित्त वर्ष में हमारी प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि केंद्र सरकार

के व्यय को चालू वित्त वर्ष की तरह जीडीपी का 3.4 फीसदी ही रखा जा सके। मगर इसके लिए सरकारी उपक्रमों का पूंजीगत व्यय कम नहीं किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार का कुल व्यय भी इस वित्त वर्ष के समान 4.5 फीसदी ही रहना चाहिए। इस सूरत में वित्त वर्ष 2026 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी के 4.5 फीसदी के उस लक्ष्य से ज्यादा रह सकता है, जो पिछले बजट में बताया गया था। ऐसा होता है तो होने दिया जाए। वास्तविक लक्ष्य है अगले वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि को 6.5 फीसदी के करीब रखना। मौजूदा अनिश्चितता के बीच निजी निवेश में कोई खास इजाफा होता नहीं नजर आता।

वित्त मंत्री ने गत वर्ष अपने बजट भाषण में संकेत दिया था कि वित्त वर्ष 2026-27 के बाद सरकार राजकोषीय घाटे को कम करने के बजाय अपने ऋण-जीडीपी अनुपात में कमी लाने पर ध्यान देगी। साफ कहें तो इसका अर्थ है राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) के तहत 3 फीसदी राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल करने के लिए दो दशकों से चल रहे निरर्थक प्रयासों को त्याग देना। अब मजबूत राजकोषीय प्रोत्साहन की जरूरत है क्योंकि मौद्रिक सहजता की गुंजाइश शायद उतनी नहीं हो, जितनी विश्लेषकों को उम्मीद थी। समस्या शायद देश के भीतर ऊंची मुद्रास्फीति बने रहने की है ही नहीं। शुल्क के मसले पर ट्रंप का रुख बताता है कि अमेरिका में मुद्रास्फीति बढ़ेगी और डॉलर मजबूत होगा। कम से कम निकट भविष्य में तो ऐसा ही होगा। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने संकेत दिया है कि 2025 में दरों में कटौती पहले के अनुमानों से कम होगी। ट्रंप के कार्यकाल के बाद अन्य अर्थव्यवस्थाओं के लिए अपनी नीतिगत दरों को फेड की दरों से अलग करना मुश्किल हो जाएगा।

बजट की दूसरी प्राथमिकता बेरोजगारी की समस्या होनी चाहिए, खास तौर पर शिक्षित बेरोजगारों का मसला। गत वर्ष बजट में तीन योजनाओं की घोषणा की गई थी, जिनका लक्ष्य था निजी क्षेत्र में रोजगार को प्रोत्साहन देना। एक इंटर्नशिप कार्यक्रम की भी घोषणा की गई थी, जिसमें पांच सालों में दो लाख करोड़ रुपये यानी सालाना 40,000 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने की बात थी। मगर बजट में केवल 12,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। **(क्रमशः ...)**

स्वस्थ माता-तंदुरुस्त बच्चा अभियान का किया गया शुभारंभ

उत्तम स्वास्थ्य समृद्धि का आधारः सीएम साय

रायपुर। माताओं एवं बच्चों का उत्तम स्वास्थ्य प्रदेश की उन्नति और समृद्धि का आधार बनेगा। माताओं एवं बच्चों का उत्तम स्वास्थ्य छत्तीसगढ़ के लोककल्याणकारी राज्य की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज जशपुर जिले के बगिया स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से आईआईटी बॉम्बे-जशपुर पोषण मिशन अंतर्गत %स्वस्थ माता- तंदुरुस्त बच्चा% अभियान का शुभारंभ करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने गर्भवती माताओं और बच्चों के पोषण स्तर को बेहतर बनाने जशपुर जिले में %स्वस्थ माता-तंदुरुस्त बच्चा% अभियान का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संयुक्त रूप से संचालित इस अभियान के तहत 9500 से अधिक स्वास्थ्य और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आईआईटी बॉम्बे के माध्यम से पोषण संबंधी ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत माताओं और बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अभियान के तहत 300 से अधिक मास्टर ट्रेनर जिले में स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के मैदानी कार्यकर्ताओं को सतत प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य जशपुर जिले में कुपोषण को पूरी तरह समाप्त करना और माताओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाना है। अभियान के तहत् गर्भवती माताओं, शिशुवती माताओं और 6 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने का लक्ष्य है। इसमें विशेष रूप से स्तनपान, पोषण आहार और पूरक आहार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस पहल के जरिए गर्भवती माताओं को सही पोषण की जानकारी दी जाएगी, जिससे बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बन सके।

मुख्यमंत्री श्री साय ने %स्वस्थ माता-तंदुरुस्त बच्चा% अभियान की सराहना करते हुए कहा कि यह पहल जिले में स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूकता को बढ़ाएगी, साथ ही कुपोषण को खत्म करने और गर्भवती माताओं, शिशुवती माताओं तथा 6 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाने में सहायक होगी।

बाबू भैया की कलम से

सरकार का सुशासन पर गंभीर आरोपों के संकट

विष्णुदेव सरकार के सुशासन के प्रचार के बीच स्थानीय चुनावों के आरक्षण में ओबीसी की घोर उपेक्षा और सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार की घटनाओं ने दाग लगा दिया है। इन मुद्दों ने विपक्ष को सरकार पर वार करने के लिए बैठे बिठाए राजनैतिक हथियार उपलब्ध करा दिए हैं। घात -प्रतिघात के दौर राजनैतिक मंच पर शुरू हो गये हैं। पहले सड़क निर्माण में गड़बड़ी व भ्रष्टाचार के समाचार सामने आये। बीजापुर के एक पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने एक ठेकेदार के द्वारा सड़क निर्माण में की जा रही बड़ी गड़बड़ी को उजागर कर दिया। सरकार ने व उसके पुलिस प्रशासन ने तो कुछ कार्यवाही नहीं की लेकिन ठेकेदार व उनके गुर्गों नें पत्रकार की नृशंस हत्या कर उसे अपने परिसर में स्थित सेफ्टी टैंक में दफन कर दिया। कहा जा सकता है कि उसे सीमेंट से चिनवा दिया। सरकार कुछ करती उसके पहले बीजापुर के पत्रकारों ने अगवाई कर पुलिस को जागने को मजबूर किया। पत्रकार का शव बरामद किया गया। पूरे देश -दुनिया में इस हत्या कांड की जितनी गूंज हुई उससे ज्यादा सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग के इस भ्रष्टाचार की गूंज देश दुनिया में गई। सरकार के कथित सुशासन की तरह तरह से चर्चा हुई। लोगों ने कहा यह कैसा सुशासन ? बीजापुर तो चलो उस बीहड़ क्षेत्र में स्थित है जहां कहा जाता है कि ,शासन प्रशासन की पकड़ नहीं के बराबर है। वहां की घटना कोई जाबांज पत्रकार ही उठाने की हिम्मत कर सकता है। ना जाने कितने मामले वहां इस तरह के हो रहे होंगें जिसे उठाना पत्रकार के बस में भी ना हो। वहां क्या चल रहा होगा,यह आसानी से समझा जा सकता है। विभागीय अधिकारियों व ठेकेदारों के अवैध गठबंधन प्रदेश भर में इसी तरह सरकार पर पलीता लगाने का ही काम कर रहे होंगें। यह समझा जा सकता है। बीहड़ों के बाहर आकर देखें तो अब राजधानी जहां जिम्मेदार आला अफसरों से लेकर अति जिम्मेदार मंत्रिमंडल के सभी सदस्य निवास करते हैं। अपने महंगे वाहनों से नित्यप्रति सड़के नापते रहते हैं। वहां वीआईपी के आवागमन के मार्ग पर पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई जा रही घटिया सड़क की पोल खोलने की हिम्मत ,अपनी जान की परवाह ना करते हुए एक पत्रकार ने ही की। सरकारी अमला तो आंख मूंद कर बैठा था। निर्माण स्थल पर सिर्फ ठेकेदार के गुर्गे ही मौजूद रह कर लीपापोती करते रहे। 7 दिन तक सड़क की आवाजाही बंद कर धड़ल्ले से यह काम होता रहा। पत्रकार की नजर से नहीं बचा। उसने सारी गड़बड़ी को सरकार के सामने अपने चैनल के माध्यम से उजागर करते हुए सरकार को जगाया। पीडब्ल्यू मिनिस्टर तत्काल सतर्क हुए घटना स्थल पर पहुंचे। निश्चित ही उनकी बहुत प्रसंशा हुई। उन्होंने बाकायदा ठेकेदार से डांटते हुए सबके सामने पूछा कि कभी सड़क बनाए हो। ठेकेदार ने कह दिया साहब फिर से बना देंगें। मंत्री जी ने सरकारी अधिकारियों को निर्देश दिए और बंगले पर वापस आ गए। ठेकेदार ने फिर भी मानक से सड़क नहीं बनाई और जानकारी के अनुसार मौके पर मौजूद अधिकारियों की भी नहीं सुनी। मनमानी तरीके से काम कर दिया। अब सवाल यह उठता है की जब राजधानी की सड़को में यह किया जा सकता है तो ठेकेदारों की हिम्मत व संबंधितों के आचरण को समझा जा सकता है। बीहड़ों में नक्सल क्षेत्र में हो रहे निर्माण का क्या हाल होगा सरकार ही समझेगी,और किसी के समझ में तो आएगा नहीं। जनता के टैक्स के पैसे का यह दुरुपयोग रोकने के लिए अब भगवान ही मालिक है। यह नहीं कि यह वर्तमान सरकार में ही हो रहा है सभी सरकारों में यही सिस्टम काम करता है।

साय सरकार पर दो और प्रश्न खड़े किये गए हैं। एक तो बड़ी शान से जिन्होंने बैलेट पेपर से नगरीय निकाय चुनावों को कराने की बात करके विपक्ष से भी अपनी पीठ ठोकवाने का काम किया था,उन्होंने ही बिना शर्मिंदगी से कुछ दिनों बाद ही कह दिया कि अब ईवीएम से ही चुनाव होंगें। जनता व विपक्ष सोचते ही रह गये कि यह अचानक परिवर्तन क्यों हुआ ? कोई कह रहा है कि बैलेट पेपर से सरकार को कुछ खतरे का आभास हुआ होगा। ईवीएम से कुछ अदृश्य वरदान मिलने की आशा में यह हुआ है। कोई कहता है कि ईवीएम में कोई खास राज छुपा हुआ है ,यानी जनता के बीच एक बार फिर ईवीएम संदेह के घेरे में आने को उत्सुक है। देखना होगा कि आखिर ये राज है क्या ? परिणाम बहुत कुछ इशारा कर ही देगा। विपक्ष ईवीएम को घेरने को अभी से तैयार है। इसके अलावा सरकार नगरीय निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर भी घेरे में आई है। ओबीसी वर्ग को आरक्षण से एकदम बाहर किया जाना चर्चा में है। आखिर यह क्या सोच कर किया गया। सरकार ओबीसी को 50 प्रतिशत आरक्षण देने के पोस्टर लगवा कर वाहवाही लूट चुकी है। अब वह कैसे इस वर्ग से गुरेज करने लगी। एक सीट भी ओबीसी को आरक्षण नहीं देना सरकार की मंशा पर प्रश्नचिन्ह लगा रहा है। सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि कोई बात नहीं हम सामान्य सीट पर ओबीसी को टिकट देंगें। अब सवाल यह आता है कि जब सामान्य सीट से देने तैयार हैं तो उन्ही को आरक्षण देने में क्या दिक्कत थी। यह भी कि सामान्य सीट से जीत मिलेगी या नहीं। ओबीसी बाहुल्य सीट पर अलग बात होती है सामान्य सीट पर अलग बात।ऐसी स्थिति में सुशासन की बात करके अपनी पीठ थपथपाने वाली इस सरकार पर जनता कैसे विश्वास करे कि यह साय के सुशासन की सरकार चल रही है। सरकार विश्वास के संकट से गुजर रही है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान 17 कोः खूबचंद पारख

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा आगामी 17 जनवरी को होगी। इसके लिए कल 16 जनवरी को शाम 5 से 7 बजे तक नामांकन होगा। यह जानकारी प्रदेश संगठन चुनाव प्रभारी खूबचंद पारख ने दी और बताया कि प्रदेश अध्यक्ष पद का निर्वाचन सम्पन्न कराने भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े विशेष तौर पर सम्मिलित होने आ रहे हैं। तावड़े के साथ ही भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन और चुनाव पर्यवेक्षक गजेंद्र पटेल भी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान राजधानी में रहेंगे।

भाजपा प्रदेश संगठन चुनाव प्रभारी पारख ने कहा कि पूरे देश के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी सितम्बर-2024 से संगठन महापर्व मनाया गया, जिसमें पहले सदस्यता महाअभियान चलाया गया। छत्तीसगढ़ भाजपा को 60 लाख सदस्यता का जो लक्ष्य केंद्रीय नेतृत्व ने दिया था, उस लक्ष्य को अर्जित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष किरणसिंह देव, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय के मार्गदर्शन में भाजपा सरकार के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, भाजपा व सभी मोर्चा-प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों-कार्यकर्ताओं व समस्त जनप्रतिनिधियों ने परिश्रम की पराकाष्ठा करके इस अभियान को सर्वसमावेशी और सर्वस्पर्शी बनाया। सदस्यता अभियान में समाज के हर वर्ग और सुदूर क्षेत्रों तक पहुँचकर उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई गई। भाजपा के इस ऐतिहासिक संगठन महापर्व सक्रिय सदस्यता अभियान भी युद्धस्तर पर चला। पारख ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली प्रदेश की भाजपा सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों, कार्यक्रमों व योजनाओं के साथ मोदी के नेतृत्व के प्रति जन आकर्षण के चलते भाजपा ने छत्तीसगढ़ में सदस्यता अभियान में इतिहास रचा और पूरे प्रदेश की 35 प्रतिशत आबादी ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है, जो भाजपा की लोकप्रियता, भाजपा के प्रति अटूट जन-विश्वास का प्रमाण है।

भाजपा प्रदेश संगठन चुनाव प्रभारी पारख ने बताया कि सदस्यता महाअभियान के बाद संगठन चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई जिसके तहत सबसे पहले बूथ कमेटियों का गठन कर बूथ अध्यक्ष बनाए गए। बूथों के बाद मंडल अध्यक्ष की घोषणाएँ हुई। इसके बाद सारे 36 संगठन जिलों में जिला अध्यक्ष भी घोषित कर ले गए। अब आगामी 17 जनवरी को प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन होने जा रहा है। इसके लिए 16 जनवरी की शाम 5 से 7 बजे तक नामांकन जमा होगा। संगठन महापर्व के दौरान चले सदस्यता अभियान और बूथ से लेकर जिला अध्यक्ष तक की चुनाव प्रक्रिया के सफल संचालन की दिल्ली में हुई समीक्षा बैठकों में भी बहुत ज्यादा प्रशंसा हुई है।

लूट के असली सरगना भूपेश बघेल है और कवासी मोहरा : कश्यप

रायपुर। प्रदेश के वन और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी पर कहा है कि लखमा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के षड्यंत्रों का शिकार हैं। श्री कश्यप ने कहा कि बघेल ने अपने घोटालों को अंजाम देने के लिए लखमा को मोहरे के तौर इस्तेमाल किया।

प्रदेश के वन मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि शराब का पूरा घोटाला भूपेश बघेल की सरपरस्ती में हुआ और बघेल ने जन-धन की लूट मचाकर छत्तीसगढ़ को गांधी परिवार का एटीएम बनाया और यह पैसा सोनिया-राहुल तक भी गया। श्री कश्यप ने कहा कि कवासी लखमा को जान-बूझकर आबकारी मंत्री बनाया था ताकि वह इस घोटाले को अंजाम दे सकें। यह एकदम साफ है कि भूपेश बघेल ही शराब घोटाले के प्रमुख घोटालेबाज हैं और कवासी लखमा को इसमें एक मोहरे के तौर पर फँसाया गया है। शराब समेत तमाम घोटाले करने की बघेल ने बड़ी लंबी प्लानिंग कर रखी थी, इसमें सहयोगी बने लखमा अब इसकी कीमत चुका रहे हैं। इससे पहले भी जो गिरफ्तार हुए हैं, वह सब भी भूपेश बघेल के करीबी लोग हैं और जमानत के लिए एड़ियाँ घिस रहे हैं। श्री कश्यप ने कहा कि घोटालों के किंगपिन और पॉलीटिकल मास्टर तक जांच एजेंसियों के हाथ पहुचेंगे ही। प्रदेश की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले, उन्हें नकली और घटिया शराब तक परोसने वालों को उनके किये की सजा मिलकर रहेगी।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

प्रदेश में 124 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में प्रदेश के किसानों से सुगमता पूर्वक धान की खरीदी की जा रही है। वहीं धान खरीदी व्यवस्था पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। राज्य में 14 नवम्बर से शुरू हुए धान खरीदी का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। अब तक लगभग 124 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी हो चुकी है। प्रदेश के 23 लाख किसानों ने धान बेच चुके हैं। अभी तक बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत 25 हजार 549 करोड़ रूपए किसानों को भुगतान किया गया है। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगी।प्रदेश के समस्त पंजीकृत कृषकों को खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान विक्रय हेतु टोकन की सुविधा ऑनलाईन एप्प (टोकन तुंहर हांथ) एवं उपार्जन केन्द्रों में 25 जनवरी 2025 तक के लिए उपलब्ध कराया गया है। किसान सुविधा अनुसार तिथि का चयन कर नियमानुसार धान विक्रय कर सकते है।धान खरीदी के साथ-साथ मिलर्स द्वारा धान का उठाव भी तेजी से हो रहा है। अब तक 94 लाख मीट्रिक टन धान के उठाव के लिए डीओ और टीओ जारी किया गया है, इसके एवज में 67 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव कर लिया गया है।गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा इस खरीफ वर्ष के लिए 27.78 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। इसमें 1.59 लाख नए किसान शामिल है।

चुनाव के कारण बच्चों के परीक्षा पर असर पड़ेगाः शुक्ला

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि भाजपा सरकार स्थानीय निकाय चुनाव में जाने से डर रही है, और सरकार के डर के कारण है चुनाव मे देरी हो गयी अब 10 वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तिथि जारी होने के बाद परीक्षा और चुनाव टकरा रहा दोनों मे से किसी एक को बढ़ाना ही पड़ेगा। विगत 13 महीना से अधिक हो गया सरकार में आए, दिसंबर 2024 से पहले स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न हो जाना था, लेकिन जानबूझकर लंबित रखा गया। सीबीएसई, आईसीएससी और स्टेट बोर्ड की 10 वीं, 12वीं की तमाम परीक्षाएं 14 फरवरी से लेकर अप्रैल तक होनी है। समय पर चुनाव कराने की अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी पर अब तक आंख मूंदे बैठी यह सरकार स्थानीय निकाय चुनाव और बोर्ड परीक्षाओं की तिथि टकराकर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। सरकार या तो परीक्षा आगे बढ़ाये या चुनाव आगे बढ़ाये। सीबीएससी, इ्रष्टस्ष्ट बोर्ड, छ.ग. बोर्ड सभी के परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है। चुनाव के समय परीक्षा चल रही होगी तब मतदान के लिए शिक्षको की ड्यूटी लगाई जाएगी उससे भी बच्चो की पढ़ाई पर असर पड़ेगा। भाजपा सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों को बिलम्ब कर यह टकराव की स्थिति निर्मित किया है।

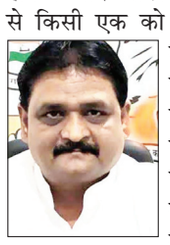

ननि चुनाव में भाजपा को करारी हार दिख रहीः ठाकुर

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस नेताओं पर प्राणघातक हमला किया है। गुंडागर्दी की है यह बेहद निंदनीय और अलोकतांत्रिक है कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि तत्काल शिवरतन शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए और असंवैधानिक कार्य करने वाले पालिका के प्रशासक को हटाया जाए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाये। भाजपा को आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में अपनी करारी हार दिख रही है इसलिए भाजपा नेता बौखलाहट में कांग्रेस नेताओं पर हमला करवा रहे हैं गुंडागर्दी कर रहे हैं लोकतंत्र की गला घोट रहे हैं। प्रदेश के निकायों में प्रशासक नियुक्त किया गया है जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो गया है उसके बावजूद भाटापारा नगर पालिका के प्रशासक ने किस नियम के तहत पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा जो वर्तमान में किसी पद में नहीं है उन्हें लोकार्पण के लिए आमंत्रित किया जबकि यह अधिकार स्थानीय विधायक का है।कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया तो भाजपा नेता पूर्व विधायक शर्मा ने भाजपा के गुंडों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमला किया है।

ओबीसी आरक्षण की रक्षा करने में असफल साव इस्तीफा देः वर्मा

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेन्द्र वर्मा ने कहा कि ओबीसी आरक्षण की रक्षा करने में असफल डिप्टी सीएम अरुण साव को अपने पद से तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिये। उपमुख्यमंत्री अरुण साव को खुद को ओबीसी वर्ग का हितैषी बताते है, लेकिन उनकी सरकार ने ओबीसी आरक्षण जिला पंचायतों में खत्म कर दिया है। ओबीसी वर्ग के साथ हुये अन्याय पर अरुण साव मौन क्यों है? उन्हें तत्काल ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिलाना चाहिये, अन्यथा उन्हें उपमुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिये।भाजपा की सरकार ओबीसी विरोधी है इसलिये दुर्भावना पूर्वक साय सरकार ने प्रदेश के सभी जिला पंचायतों में ओबीसी आरक्षण को खत्म कर दिया है। 2019 में कांग्रेस सरकार के दौरान प्रदेश में 27 जिला पंचायत में उस दौरान 7 जिला पंचायत ओबीसी वर्ग के लिये आरक्षित था, वर्तमान में 33 जिलों में 1 भी जिला पंचायत अध्यक्ष का पद ओबीसी के लिये आरक्षित नहीं है। साव कह रहे है कि ओबीसी वर्ग को लाभ हुआ है तो उन्हें यह बताना चाहिये कि 33 जिलों में ओबीसी के लिये शून्य सीटें, ये कैसा लाभ? न केवल नगरीय निकाय बल्कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी आरक्षण प्रक्रिया में संशोधन करके साय सरकार ने ओबीसी वर्ग के लोगो को चुनाव लड़ने से वंचित किया है।

हर एक भ्रष्टाचारी का सही स्थान जेल ही हैः श्रीवास्तव

रायपुर। भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि हर एक भ्रष्टाचारी का स्थान जेल ही है निश्चित ही इसमें कोई संदेह नहीं है जनता से झूठे वादे और प्रलोभन देकर सत्ता में आई कांग्रेस की सरकार के समय छत्तीसगढ़ में बड़ी लूट हुई, धीरे-धीरे उसकी परते खुल रही है। चाहे रेत घोटाले की बात हो,माइनिंग हो या शराब घोटाले की बात हो,सभी प्रकार के घोटालों में कांग्रेस के करीबी भ्रष्ट अधिकारी और कांग्रेस के नेता जेल जा रहे है। अधिकारियों की संलिप्तता के बाद अब पूर्व आबकारी मंत्री व उनके रिश्तेदारों की संलिप्तता भी सामने आ रही है। श्री श्रीवास्तव ने कहा गलत कृत्य करने वालों की गिरफ्तारी हो रही है लेकिन इन सबके पीछे,इस पूरे षड्यंत्र का सरगना कोई और है जिस पर सबकी निगाहें,जनता भी जान रही है इस षडयंत्र के पीछे कौन है।भाजपा ने चुनावों के पहले जनता से वादा किया था भ्रष्टाचार के मामले पर जीरो टॉलरेंस की नीति होगी।चाहे पी एस सी घोटाला हो,शराब घोटाला हो या अन्य किसी घोटाले की बात हो हर एक अधिकारी जेल की सलाखों के पीछे जा रहा है यही विष्णु देव साय का सुशासन है और यही हमारी भ्रष्टाचार के खिलाफ नीति है हर भ्रष्टाचारी जेल की सलाखों की पीछे जा रहा है।

पूंजीगत व्यय के सदुपयोग में छत्तीसगढ़ ने देश में बनाई अलग पहचान

छत्तीसगढ़ को केंद्र से मिलेगा 1874 करोड़ अतिरिक्त आबंटन

पूँजीगत व्यय के प्रभावी उपयोग के लिए छत्तीसगढ़ की केंद्र सरकार ने की सराहना

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी जनहितैषी नीतियों एवं कार्यक्रमों से न केवल प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, अपितु राज्य के बजट और केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि का जनहित में सदुपयोग सुनिश्चित कर केंद्र सरकार से सराहना और प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने की भी हकदार बनी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का कहना है कि राज्य की जनता को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना और विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाना सरकार की प्राथमिकता है।

छत्तीसगढ़ ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजीगत व्यय के तहत आबंटित धनराशि का कुशल और प्रभावी उपयोग किया है, जिसकी केंद्र सरकार ने सराहना की है। पूंजीगत व्यय के तहत राशि के सदुपयोग के परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य को शीघ्र ही 1874 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आबंटन मिलेगा। यह राशि राज्य के बुनियादी ढांचे और अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए खर्च की जाएगी।

पूंजीगत व्यय यानि कैपिटल एक्सपेंडिचर (कैपेक्स) का अर्थ है उन पूंजीगत व्ययों का प्रावधान, जो किसी राज्य या देश में बुनियादी ढांचे के निर्माण, नए परिसंपत्तियों के सृजन और दीर्घकालिक विकास के लिए किए जाते हैं। बजट में इसे इसलिए शामिल किया जाता है ताकि शासकीय धन का उपयोग सड़क, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, और उद्योग जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण और विकास के लिए किया जा सके।पूंजीगत व्यय यानि कैपिटल एक्सपेंडिचर (कैपेक्स) का अर्थ है उन पूंजीगत व्ययों का प्रावधान, जो किसी राज्य या देश में बुनियादी ढांचे के निर्माण, नए परिसंपत्तियों के सृजन और दीर्घकालिक विकास के लिए किए जाते हैं। बजट में इसे इसलिए शामिल किया जाता है ताकि सरकारी धन का उपयोग सड़क, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, और उद्योग जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण और विकास के लिए किया जा सके।

छत्तीसगढ़ सरकार का उद्देश्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और राज्य के समग्र विकास को गति देना है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय (राज्य कैपेक्स) में 17,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह राशि सड़कों, पुलों, स्कूलों, अस्पतालों, औद्योगिक परियोजनाओं और सिंचाई योजनाओं पर खर्च की जा रही है। राज्य को केंद्र से 1874 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन मिलने से नई परियोजनाओं को लागू करने, रोजगार सृजन और राज्य के बुनियादी ढांचे को और अधिक सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार का उद्देश्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और राज्य के समग्र विकास को गति देना है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय में 17,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में कटौती के खिलाफ कांग्रेस का एकदिवसीय प्रदर्शन

रायपुर । भाजपा सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में कटौती के खिलाफ कांग्रेस ने एकदिवसीय प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा यह प्रदर्शन सुभाष स्टेडियम फायर ब्रिगेड चौक के पास रखा गया था जिसमें कांग्रेस के तमाम नेता गण उपस्थित थे।

कांग्रेस के नेताओं ने हाथों में तख्ती लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की इस अवसर पर शहर अध्यक्ष गिरीश दुबे ने कहा कि केंद्र और राज्य में बैठी भाजपा सरकार संविधान विरोधी तो है ही लेकिन आज पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में कटौती कर उन्होंने यह साबित कर दिया कि वह पिछड़ा वर्ग आरक्षण विरोधी भी है। भाजपा सरकार दावा करती है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार कार्य किया है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार पिछड़ा वर्ग को मिलने वाला आरक्षण के अनुसार नगरी निकाय एवं त्रिस्तरी पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण नहीं दिया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भाजपा सरकार पिछड़ा वर्ग विरोधी है। इस प्रदर्शन में प्रमोद दुबे एजाज ढेबरकुमार मेनन सूर्यमणि मिश्रा प्रमोद चौबे मदन तालेडा शिव सिंह ठाकुर सुरेश ठाकुर अजय साहू सुमित दास सुंदर जोगी नवीन चंद्राकर प्रशांत ठेंगड़ी देव कुमार साहू धनंजय ठाकुर जी श्रीनिवास बंशी कन्नौजे दिनेश ठाकुर सचिन शर्मा दीपा बग्गा देवेंद्र यादव कामरान अंसारी ममता राय मुन्ना सोनकर चितरंगा साहू मोहम्मद फहीम आदि मौजूद थे।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.